चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 24 अक्टूबर- 30 अक्टूबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उरी आतंकी हमले की सच्चाई

मनीष कुमार

ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है और न ही सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले पर कोई वास्तविक विश्लेषण करने में इच्छुक है. अगर कोई करता होता तो उरी जैसा आतंकी हमला नहीं होता. सुरक्षा जैसे गंभीर मामले में भी सरकार के जिम्मेदार लोग अनर्गल बयानबाजी और एक दूसरे की पीठ थपथपाने में जुटे हैं. मंत्री हों या अधिकारी सब क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हैं. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तो गैरजिम्मेदार-बयानबाजी की सारी हदें लांघ दी हैं. टीवी स्टूडियो और जनसभाओं में सरकार की सुरक्षा-नीति का खुलेआम ढिंढोरा पीटने की नई प्रथा शुरू हो गई है. जिन बातों को प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय या गृहमंत्रालय से बाहर नहीं आना चाहिए, उन बातों को भी सार्वजनिक रूप से बोलने में कोई पीछे नहीं है.

ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता को अभी तक समझ नहीं पाए हैं. जिन लोगों पर सैन्य-प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का विश्लेषण और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है, वो या तो स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनमें काबिलियत ही नहीं है. यही वजह है कि वो सही फैसले नहीं ले रहे हैं. सैन्य-प्रतिष्ठानों को कैसे अभेद्य बनाया जाए, इस पर न तो कोई सोच रहा है और न ही कोई रणनीति है. सब कुछ लुंज-पुंज चल रहा है. इसका नतीजा ये है कि हम आतंकी हमले को रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. अगर हम पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर हुए हमले के बाद भी संभल नहीं पाए, तो ये चिंता की नहीं, बल्कि शर्म की बात है. पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में बेरोकटोक घुसने और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने में लगातार सफल हो रहे हैं. वो भी ऐसे समय में, जब देश को यह बताया जा रहा है कि कश्मीर में सेना हाई एलर्ट पर है.

उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर 18 सितंबर 2016 को आतंकी हमला हुआ था. हमला एक ऐसे परिदृश्य में हुआ, जब पूरे कश्मीर घाटी में अशांति थी. आतंकी बुरहान वानी की हत्या के बाद 8 जुलाई 2016 से ही कश्मीर में रोजाना हिंसक झड़पें हो रही थीं. बुरहान वानी की मौत के बाद से ही हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और मसूद अजहर पाकिस्तान से लगातार धमकियां दे रहा था कि वे बुरहान वानी की मौत का बदला लेंगे. ये आतंकी खुलेआम हमले की धमकी दे रहे थे. पाकिस्तान में भी कश्मीर का मुद्दा गरम था. वहां का मीडिया, राजनीतिक दल और सेना लगातार कश्मीर के मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे थे. पाकिस्तान की सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के जनरल एसेंबली में उठाने का फैसला कर लिया.

वैसे भी सितंबर का महीना था, बर्फ पड़ने से पहले सीमा पार से घुसपैठ ज्यादा होती है. ऐसे माहौल में आतंकी हमले का खतरा कितना बढ़ जाता है, यह समझने के लिए रक्षा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है. जो कोई भी आतंकी हमले की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, उसे पता है कि हर बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के पहले आतंकी हमला करते हैं. दूसरी बात यह कि पिछले कई आतंकी हमलों से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. आतंकी आमलोगों यानी बाजार या भीड़भाड़ वाले इलाकों को छोड़ कर अब सैनिक-प्रतिष्ठानों पर हमला करने लगे हैं. इसके बावजूद अगर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला होता है और सैनिक मारे जाते हैं, तो इसे एक आपराधिक चूक ही माना जाएगा. अब सवाल यह है कि उरी में भारतीय सेना से कहां और किस स्तर पर चूक हुई?

उरी में जो हुआ, उसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसे हम कमांड एंड कंट्रोल का पूरी तरह से फेल हो जाना कह सकते हैं. ऐसा लगता है कि उरी ब्रिगेड मुख्यालय में न तो किसी को खतरे का आभास था और न ही सुरक्षा की चिंता थी. हमले की खुफिया जानकारी पहले से थी, फिर भी जिम्मेदार लोग वस्तुतः सोये हुए थे. हमले का खतरा सर पर मंडरा रहा था, लेकिन ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारी गोल्फ खेलने में व्यस्त थे. न पहरा बढ़ाया गया, न ड्यूटी में कोई बदलाव किया गया, न चौकसी बढ़ाई गई, कुछ भी नहीं किया गया. हकीकत तो ये है कि उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी मानक संचालन प्रक्रिया का भी पालन नहीं हो रहा था. हाई एलर्ट की स्थिति तो दूर, आमतौर पर शांति के समय सेना द्वारा की जाने वाली साधारण कार्य-प्रणाली का भी पालन नहीं हो रहा था.

यह कहा जा सकता है कि आतंकियों ने उरी हमला नहीं किया, बल्कि इस ब्रिगेड ने अपनी अकर्मण्यता से हमले को न्यौता दिया. समझने वाली बात यह है कि हर शाम सेना को खुफिया जानकारी दी जाती है. ये रूटीन कार्य है. हर शाम लोकल कमांडर को बताया जाता है कि ये खतरा है और चौकन्ना रहने की जरूरत है. उरी हमले के कुछ दिन पहले पुंछ में ऐसा ही हमला हुआ था. उस हमले की भी खुफिया जानकारी थी, लेकिन पुंछ की पलटन चौकस थी, इसलिए जब आतंकियों ने हमला किया तो जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया. पुलिस के एक जवान शुरू में शहीद जरूर हुए लेकिन सेना ने आतंकियों को बाहर ही मार गिराया. लेकिन उरी में क्या हुआ?

उरी में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो पूरा ब्रिगेड सो रहा था. उरी हमले के वक्त ब्रिगेड कमांडर सोमा शंकर थे. अब उन्हें उरी से हटा दिया गया है. बताया ये जाता है कि उरी के ब्रिगेड कमांडर साहब का ब्रिगेड के कामकाज से ज्यादा ध्यान गोल्फ खेलने में रहता था. इनके बारे में धारणा तो ये थी कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, इसलिए उनके क्रियाकलापों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है. ब्रिगेड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिगेड कमांडर की होती है. उनकी यह ड्यूटी होती है कि वो ब्रिगेड के अंदर हर क्रियाकलापों पर नजर रखें और जहां कहीं भी गड़बड़ी हो, उसे ठीक करें. ब्रिगेड में चहारदीवारी कितनी सुरक्षित है, चौकसी कैसी है, दिन और रात में ड्यूटी पर कितने लोग हैं? मतलब यह कि ब्रिगेड की सुरक्षा की स्थिति और चौकसी का जायजा लेना और योजना बनाने का दायित्व ब्रिगेड कमांडर का होता है.

आमतौर पर शाम साढ़े छह बजे खुफिया जानकारी पर बातचीत और कहां, कैसे, किसकी ड्यूटी होगी, ये तय होता है. वैसे भी उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर कश्मीर में है और तनावपूर्ण स्थिति है, इसलिए यहां तो और सतर्कता की जरूरत थी. सेना के एक सूत्र के मुताबिक उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पूरी तरह से ढिलाई बरती गई थी. ब्रिगेड कमांडर को इन जरूरी कामों में रुचि नहीं थी. बाकी चौकसी रखना तो दूर, ब्रिगेड कमांडर का ध्यान इस पर भी नहीं गया कि ब्रिगेड मुख्यालय के आसपास और चहारदीवारी से (शेष पृष्ठ 2 पर)

उरी में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो पूरा ब्रिगेड सो रहा था. उरी हमले के वक्त ब्रिगेड कमांडर सोमा शंकर थे. अब उन्हें उरी से हटा दिया गया है. बताया ये जाता है कि उरी के ब्रिगेड कमांडर साहब का ब्रिगेड के कामकाज से ज्यादा ध्यान गोल्फ खेलने में रहता था. इनके बारे में धारणा तो ये थी कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, इसलिए उनके क्रियाकलापों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है. ब्रिगेड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिगेड कमांडर की होती है.

नौकरियां घट रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है | P-3

कलह और कलुष के दलदल में सभी दल | P-6

शहाबुद्दीन को लेकर लालू कठघरे में | P-7

उरी आतंकी हमले की सच्चाई

पृष्ठ 1 का शेष

सटे कई जगहों पर लंबे-लंबे घासों की सफाई भी जरूरी है. वो इसलिए क्योंकि इन लंबे घासों के अंदर कोई भी छिप सकता है. मौका पाकर अंदर दाखिल हो सकता है. यह तो लापरवाही की पराकाष्ठा है क्योंकि कश्मीर की स्थिति को देखते हुए आतंकी हमले का खतरा हर सैन्य प्रतिष्ठानों पर मंडरा रहा था. इस खतरे की तस्दीक हर दिन मिलने वाले खुफिया रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही थी. सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि खतरे की जानकारी मिलने के बाद ब्रिगेड कमांडर ने क्या किया? खतरे से निपटने के लिए ब्रिगेड कमांडर ने क्या आदेश दिए?

समझने वाली बात यह है कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट या फिर कोई जगह, आमतौर पर हर पलटन में सवेरे चार बजे से ही हलचल शुरू हो जाती है. वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जगहों पर शौचालय की कमी होती है. सेना में हर किसी को हर दिन सेविंग करनी होती है. ठंडे इलाकों में गरम पानी की जरूरत होती है. वर्दी तैयार करना होता है. सूर्योदय से पहले सबलोग तैयार हो जाते हैं. मेस में नाश्ते के लिए भी जाना होता है. ये सब वहां होता है, जहां अनुशासन होता है. स्वयं अधिकारी भी अनुशासन का पालन करते हैं. अगर किसी ब्रिगेड में ऊपर से लेकर नीचे तक अनुशासनहीनता और समय का पालन न होता हो तो उरी जैसी स्थिति पैदा होना लाजिमी है. उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर की जगह अगर कोई दूसरी जगह होती तो साढ़े पांच बजे जवान व अधिकारी जगे हुए मिलते. जिस तरह उरी में आतंकियों को सब लोग सोते हुए मिले, वैसा नहीं होता. वो तो ऊपरवाले का शुक्र है कि आतंकवादी ब्रिगेड के अंदर हमला करते हुए खाली बैरक में घुस गए. और वहीं पर भारतीय सेना ने उन्हें घेर लिया, वरना और भी ज्यादा नुकसान होता.

बताया ये जाता है कि उरी के 12 ब्रिगेड में चहेते अधिकारी को भेजा जाता है. यहां वैसे ही अधिकारी को ब्रिगेड कमांडर बना कर भेजा जाता है जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का नजदीकी या सेनाध्यक्ष का पसंदीदा ऑफिसर हो. सेना में इसे पोस्टिंग ऑफ च्वाइस कहा जाता है. उरी ब्रिगेड मुख्यालय शहर से बिल्कुल सटा हुआ है. यह श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है. दो घंटे में उरी से श्रीनगर पहुंचा जा सकता है. मतलब यह कि दो घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और एक घंटे की उड़ान से दिल्ली आ सकते हैं. पहले कभी इस इलाके में आतंकी गतिविधियां नहीं होती थीं. वो इसलिए क्योंकि इस ब्रिगेड में काम कम और मजा ज्यादा है.

बताया ये जाता है कि वर्तमान ब्रिगेड कमांडर पूर्व मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला के नजदीकी थे. वो इनके स्टाफ ऑफिसर रहे हैं. यही वजह

है कि ब्रिगेड कमांडर को राजीव भल्ला ने ही नियुक्त किया था. ये वही अधिकारी हैं, जिन पर प्रमोशन के लिए घूस लेने का आरोप है. उरी के ब्रिगेड कमांडर को सिर्फ हटाने से बात पूरी नहीं होती है. जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि इनकी नियुक्ति में भाई-भतीजावाद या फेवरेटिज्म का कोई खेल तो नहीं हुआ. जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि ब्रिगेड में चल रही गड़बड़ियों पर जीओसी की नजर क्यों नहीं गई? इस बात की भी पूछताछ होनी चाहिए कि वो क्या कारण थे जिसके चलते ब्रिगेड कमांडर बेरोकटोक अपनी कारगुजारी करते रहे और किसी ने उनसे पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि ब्रिगेड में क्या चल रहा है? हैरानी की तो बात ये है कि सेनाध्यक्ष कई बार कश्मीर का दौरा कर चुके हैं. क्या उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि किसी ब्रिगेड में क्या चल रहा है?

अब सवाल उठता है कि ब्रिगेड कमांडर ने क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (सामान्य कार्य विधि) का पालन किया? डीजल-पेट्रोल के ढेर के बगल में सैनिकों के टैंट लगाने की अनुमति किसने दी? क्या 6 बिहार रेजीमेंट के जवानों को डीजल-पेट्रोल के ढेर के बगल में रखने का आदेश ब्रिगेड कमांडर ने दिया था? ये तो कॉमनसेंस की बात है कि जहां पर ज्वलनशील पदार्थों को रखा गया हो, वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहनी चाहिए, लेकिन यहां तो टैंट बनाकर सैनिकों को अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था कर दी गई.

आतंकवादियों की योजना सटीक थी. करीब साढ़े पांच बजे सुबह चार आतंकवादी भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में दाखिल हुए. ये लोग ब्रिगेड हेडक्वार्टर की परिसीमा के तार को काट कर अंदर दाखिल हुए. पहली चूक यहीं हुई. सवाल ये है कि ये तार काट के अंदर घुस गए और किसी को पता क्यों नहीं चला? जानकार बताते हैं कि सेना की ये पुरानी तकनीक है कि जहां-जहां तार का घेरा होता है, वहां तार पर बोतल और घंटी लगा देते हैं ताकि कोई भी हलचल होती है तो आवाज होने लगती है और पहरा दे रहे सैनिक को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है. यहां न तो कोई पहरा दे रहा था और न ही तार पर कोई सेफ्टी मेजर ली गई थी. ये बात और है कि हमले

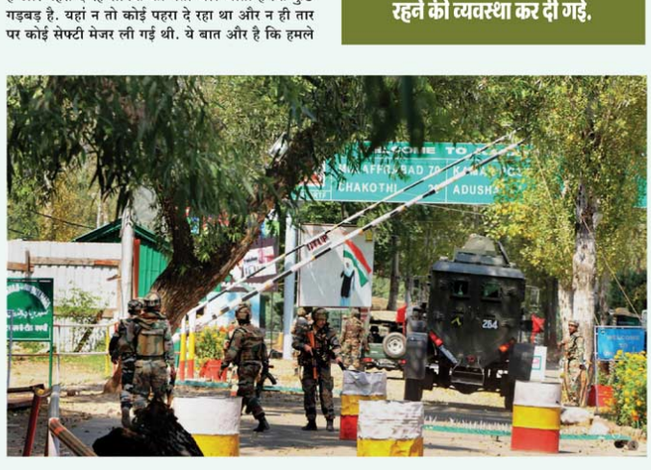

के बाद कई तथाकथित एक्सपर्ट तार में बिजली और सीसीटीवी लगाने की पैरवी कर रहे हैं. सवाल तो ये है कि युद्ध जैसी स्थिति के दौरान जब लोग सो रहे होंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा. चारों आतंकवादी आसानी से ब्रिगेड के अंदर घुस जाते हैं. उन्हें न कोई देखता है और न ही कोई चुनौती देता है.

चारों आतंकियों ने तीन मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड फेंके. धमाके की आवाज से ब्रिगेड के जवानों की नींद टूटी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. दरअसल यह हमला ऐसे मौके पर हुआ, जब इस ब्रिगेड में 6 बिहार रेजिमेंट की तैनाती हो रही थी. ये लोग 10 डोगरा रेजीमेंट की जगह लेने वाले थे. अभी पूरी तरह से लोग सेटल नहीं हुए थे, इसलिए 6 बिहार रेजीमेंट के लोगों को अस्थाई रूप से एक टैंट में रखा गया था. लेकिन यहां एक ऐसी गलती हुई, जो अक्षम्य है. जिस टैंट में बिहार रेजीमेंट के लोगों को रखा गया था, वो टैंट ठीक फुएल डम्प के बगल में था. मतलब कि ये टैंट वहां बनाया गया था जहां डीजल पेट्रोल रखा गया था. इसलिए जब ग्रेनेड से हमला हुआ तो वहां भीषण आग लग गई. ज्यादातर लोगों की मौत टैंट में आग लगने की वजह से हुई. एक तो आतंकी आसानी से अंदर घुसे, दूसरा आपने आतंकियों को बना बनाया टारगेट दे दिया. बिना गोली चलाए और बिना लड़े आतंकियों ने 17 सैनिकों की जान ले ली.

अब सवाल उठता है कि ब्रिगेड कमांडर ने क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (सामान्य कार्य विधि) का पालन किया? डीजल-पेट्रोल के ढेर के बगल में सैनिकों के टैंट लगाने की अनुमति किसने दी? क्या 6 बिहार रेजीमेंट के जवानों को डीजल-पेट्रोल के ढेर के बगल में रखने का आदेश ब्रिगेड कमांडर ने दिया था? ये तो कॉमनसेंस की बात है कि जहां पर ज्वलनशील पदार्थों को रखा गया हो, वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहनी चाहिए, लेकिन यहां तो टैंट बनाकर सैनिकों को अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था कर दी गई.

इसके अलावा, कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे कि आतंकियों को ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर की पूरी जानकारी कैसे थी? आतंकियों की योजना अकाट्य थी. उन्हें पूरी जानकारी थी कि कहां से अंदर घुसने पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी? उन्हें ये भी पता था किस वक्त अंदर घुसना है, जब सबलोग सो गए होंगे? आतंकवादियों को ये भी पता था कि कहां हमला करना है? कहां पर डीजल-पेट्रोल है और कहां पर लोग टैंट में सो रहे होंगे? जिस वक्त आतंकी अंदर घुसे उस वक्त अंधेरा था, फिर भी उनकी गतिविधि ऐसी थी जैसे वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हों. इस हमले की तहकीकात एनआईए कर रही है. शुरुआती जानकारी आते ही ब्रिगेड कमांडर को हटा दिया गया है और ये बताया गया कि उनसे कई चूक हुई है. सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेड कमांडर को हटाना इस मामले को ठंडा करने की कोशिश है. हकीकत ये है कि ब्रिगेड कमांडर का गैरजिम्मेदाराना रवैया और चूक की वजह से 20 लोगों की जान गई है. इस ब्रिगेड के अंदर होने वाली गतिविधियों से कई शर्मनाक सवाल उठने की आशंका है. एनआईए अगर ब्रिगेड कमांडर की सारी गतिविधियों की जांच और विवेचना करे और इसे सार्वजनिक करे तो उरी हमले से कई लोगों को सीख मिलेगी. उम्मीद यही है कि एनआईए अपनी जांच में दूध का दूध पानी का पानी करेगी.

ये मान भी लिया जाए कि ब्रिगेड कमांडर से चूक हुई. लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षामंत्री और सेनाध्यक्ष को क्या सही जानकारी नहीं मिल रही है. वो भी ऐसे वक्त जब कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है. सवाल तो ये भी उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी क्या है? सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हर हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है. सरकार को यह समझना होगा कि घटनास्थल पर पहुंच कर मीडिया की सुर्खियों में स्थान बनाने के बजाय हिंसक घटनाओं की जड़ में जाकर उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करना ज्यादा जरूरी है. पिछले दो साल में हुए हमलों में आम जनता से ज्यादा सैन्य-संस्थाएं आतंकवादियों के निशाने पर रही हैं. जब आर्मी ब्रिगेड और वायुसेना के एयरबेस में घुस कर आतंकी हमला करने में सफल हो जा रहे हैं तो यह देश के सुरक्षा संस्थानों के लिए चिंता की बात है.

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस की कोई चिंता ही नहीं है. कश्मीर में सौ दिन तक हंगामा होता रहा और सरकार को ये समझ में ही नहीं आया कि इससे कैसे निपटा जाए. कश्मीर में जल्द से जल्द शांति बहाल हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? कश्मीर में पहले भी हंगामा होता रहा है, लेकिन ये हंगामा शहरों में ही सीमित होता था, इस बार ये गांव तक पहुंच गया. पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे शहरों से ज्यादा कश्मीर के गांवों में लहराए गए. हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? सवाल तो ये भी उठाना चाहिए कि कश्मीर में अब हमारे पास जानकारी इकट्ठा करने वाला खुफिया तंत्र है भी या नहीं? अगर है तो इस बार घाटी से दूर-दूर बसे गांवों के लोग आंदोलित कैसे हो गए? कश्मीर में हुई चूक की जिम्मेदारी किसकी है? पहले गांवों में भारतीय सेना और केंद्र सरकार के समर्थित सरपंच और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग थे. अब ये नेटवर्क खत्म हो चुका है. यही वजह है कि कश्मीर का गांव अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ये बताना चाहिए कि राष्ट्रीय रायफल की तैनाती में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव क्यों हुए? राष्ट्रीय रायफल के ग्रिड में जो भारी बदलाव किया गया उसका विश्लेषण कौन करेगा? सुरक्षा के मामले को अगर जिम्मेदार लोग मीडिया-इवेंट बनाने लग जाएं तो देश की जनता को चिंता होना लाजिमी है. उरी हमले के बाद जो हुआ, वो यही हुआ. हमले के बाद दिल्ली और श्रीनगर के बीच हेलीकॉप्टर उड़ने लगे. सारे जिम्मेदार लोगों में मीडिया में सुर्खियां बनने की होड़ लग गई. होम मिनिस्टर हों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हों, रक्षा मंत्री या सेनाध्यक्ष, इन्हें ऐसी कौन सी जानकारी श्रीनगर में मिली जो दिल्ली में नहीं मिल सकती थी. ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ही सरकार चलाने का फैसला कर लिया है. उरी हमले की हकीकत का सही आकलन होना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो. अधिकारियों की चूक की वजह से जांबाज सैनिकों की जान चली जाए यह माफी के योग्य नहीं है. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उरी हमले के बाद भी रणनीति और योजना के स्तर पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है. बस, इतना हुआ है कि जवानों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है.■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 34
24 अक्टूबर- 30 अक्टूबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नौकरियां घट रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है

शफीक आलम

भारत में रोज़गार हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां हर साल एक करोड़ से ज्यादा नए लोग देश के कार्यबल (वर्क फोर्स) से जुड़ते हैं. ज़ाहिर है इनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना कोई आसान काम नहीं है. देश में रोज़गार उपलब्ध कराने का मसला हर पार्टी और सरकार का मुख्य मुद्दा रहा है. 2014 के आम चुनाव में भी रोज़गार मौजूदा सरकार का मुख्य मुद्दा था. अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को, खास तौर पर युवाओं को, यह यकीन दिलाया था कि यदि वे प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेंगे और हर किसी को अपने ही क्षेत्र में रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे. जनता ने उनके वादों पर भरोसा करते हुए पूर्ण बहुमत देकर उनकी सरकार तो बना दी, लेकिन देश का प्रधान बनते ही वे उन वादों को भूल गए. रोज़गार और बेरोजगारी के संबंध में भारत सरकार की संस्थान लेबर ब्यूरो द्वारा कराए गए सर्वे के आंकड़े काफी निराशाजनक हैं. लेबर ब्यूरो के ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारत की बेरोज़गारी दर पिछले पांच साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और 2009-10 के बाद इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. बेरोजगारी में वृद्धि के ये रुझान सरकार के लिए चिंता की बात है क्योंकि इसकी वजह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं.

लेबर ब्यूरो के पांचवीं वार्षिक रोज़गार-बेरोज़गारी सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2015-16 में बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह बेरोजगारी दर वर्ष 2009-10 के बाद सर्वाधिक है. वर्ष 2009-10 में बेरोजगारी दर 9.3 प्रतिशत तक थी, जो 2011-12 में घट कर 3.8 प्रतिशत रह गई थी. मौजूदा सर्वे में एक चिंताजनक रुझान यह भी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. सर्वे के मुताबिक, पुरुषों में बेरोजगारी दर 4 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं में 8.7 प्रतिशत है. इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बेरोजगारी दर कम है. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोज़गारी दर 7.8 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 12.1 प्रतिशत है. कुल मिला कर देखा जाए तो पिछले दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि शहरी क्षत्रों में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है. वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिशत थी जो 2015-16 में बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई है. वहीं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2013-14 में 5.5 प्रतिशत थी, जो घटकर 2015-16 में 4.7 प्रतिशत हो गई है.

बेरोजगारी दर प्रतिशत में

क्षेत्र	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	व्यक्ति
ग्रामीण	4.2	7.8	2.1	5.1
शहरी	3.3	12.1	10.3	4.9
कुल	4.0	8.7	4.3	5.0

इस सर्वे में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसके तहत तकरीबन डेढ़ लाख से अधिक परिवारों से इसका सैंपल लिया गया है. ज़ाहिर है यह बहुत बड़ा सैंपल नहीं है, लेकिन इस सैंपल से जो नतीजे निकले हैं, वे बेरोजगारी से संबंधित दूसरे सूचकांकों के नतीजों के ही अनुरूप हैं. अब एक नज़र देश के विकास दर पर डालते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या विकास दर में वृद्धि का संबंध रोज़गार से है या दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014-15 की पहली तिमाही में विकास दर 7.9 प्रतिशत थी. लेकिन रोज़गार बेरोजगारी सर्वे के आंकड़े यह साबित करते हैं कि इस विकास दर का सीधा फायदा गरीबों को नहीं हो रहा है. महिलाएं तो खास तौर पर इसमें पीछे हैं. अब यहां यह सवाल उठता है कि क्या सरकार अपना ध्यान केवल विकास पर केंद्रित कर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है? अगर इस सर्वे के नतीजों को देखा जाए तो इसका जवाब नकारात्मक होगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में अपने संबोधन में मनरेगा को कांग्रेस की विफलता का स्मारक करार दिया था. लेकिन इस सर्वे के मुताबिक मनरेगा और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना जैसे कार्यक्रमों की वजह से 24 प्रतिशत परिवारों को फायदा हुआ है. वहीं पूर्वोत्तर के तीन राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में मनरेगा से लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या 70 प्रतिशत है. इन आंकड़ों से ज़ाहिर है कि इन कार्यक्रमों को केवल राजनीतिक विरोध करने के लिए ही ख़ारिज नहीं किया जा सकता है.

सरकार के लिए चिंता की बात यह भी है कि सर्वे में बताया गया है कि देश में स्व-रोजगार करने वालों और वेतनमान पर नौकरी करने वालों की संख्या घटी है, जबकि अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है. सर्वे के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त युवाओं को उनकी शिक्षा और कौशल के अनुरूप नौकरी नहीं मिलना भी बेरोजगारी बढ़ने की एक प्रमुख वजह है. अखिल भारतीय स्तर पर 58.3 स्नातक और 62.4 प्रतिशत स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों ने कहा कि उनकी योग्यता के लिहाज़ से उनके लिए नौकरी उपलब्ध नहीं है. ये आंकड़े जहां मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और कौशल विकास पर सवाल उठाते हैं, वहीं देश की शिक्षा व्यवस्था को भी कठघरे में खड़े करते हैं. नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थकों द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि निजीकरण ही देश की सभी समस्यों से निजात दिला सकता है. उसमें शिक्षा भी शामिल था. शिक्षा का भी निजीकरण किया गया, लेकिन उसका नतीजा सबके सामने है. इसी साल जनवरी में प्रकाशित एस्पाइरिंग माइंडस नेशनल एम्प्लायोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजों से पास होने वाले 80 फीसद इंजीनियर किसी काम के नहीं हैं यानी उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है.

बहरहाल, देश में आर्थिक विकास का दर पिछले कई वर्षों के मुकाबले अपने उच्चतम स्तर पर रहा है. भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. मोदी सरकार इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन लेबर ब्यूरो द्वारा जारी रोज़गार-बेरोजगारी के आंकड़े यह साबित करते हैं कि इस विकास में गरीबों और बेरोजगारों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है. यही नहीं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (वैश्विक भुखमरी सूचकांक) में भी भारत सरकार के लिए बुरी खबर है. इस सूचकांक में 118 देशों की सूची में भारत अभी भी 97 वें पर है. इस सूची में भारत के कई पड़ोसी देश जैसे नेपाल (72वें), म्यांमार (75वें), श्रीलंका (84वें) और बांग्लादेश (90वें) की स्थिति काफी बेहतर है. पड़ोसी देशों में केवल पाकिस्तान ही है, जो भारत से नीचे 107 वें पायदान पर है. लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि सात प्रतिशत के ऊपर का विकास दर और दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है, जबतक देश 125 करोड़ की आबादी को रोज़गार के लिए दर-दर भटकना पड़े और उसके बाद भी उसकी एक बड़ी संख्या को भूखे रहना पड़े. ऐसे में सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. ■

देश का भविष्य मर रहा है

भारत शिशु मृत्यु दर में पाकिस्तान से आगे

चंदन राय

चमकीली विकास के चकाचौंध में कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी हैं, जहां तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश की किरणें अपनी ऊर्जा खो देती हैं. सवाल ये है कि जब देश का प्रधान ही 'मन की बात' में मशगूल हो, तो फिर नौनिहालों की चिंता भला कौन करे? हाल में एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका लांसेट ने पांच साल के बच्चों की मौत पर एक रिपोर्ट जारी की है. शायद हमें आश्चर्य न हो कि हम इस मामले में उन देशों के साथ खड़े हैं, जो आर्थिक विकास और ताकत में हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकते, लेकिन नौनिहालों की मौत के मामले में ऐसे देश हमारे आस-पास खड़े हैं. लासेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में 5 साल से कम आयु के शिशुओं की मौत के मामले में भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों से भी आगे है.

यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में नौनिहालों की मौत के मामले में हमारी स्थिति पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर है. नेपाल में पांच साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 36 की मौत हो जाती है, बांग्लादेश में 38 और चीन में केवल 11 की मौत होती है. वहीं भारत में एक हजार नौनिहालों में से 48 अपना पांचवां बर्थडे मनाने से पहले ही जिंदगी की जंग हार जाते हैं. इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये मौतें उन बीमारियों के कारण हुई हैं, जिनका इलाज संभव था. यूनीसेफ की रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2016' में यह कहा गया है कि 2015 में भारत में पांच साल से कम उम्र के 12.6 लाख बच्चों की मौत उन बीमारियों से हुई, जिनका इलाज हो सकता था.

देश में समय से पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं की मौत का आंकड़ा सबसे भयावह (39 प्रतिशत) है. इसके बाद निमोनिया(14.9 फीसद), डायरिया (9.8 फीसद) और सेप्सिस (7.9 फीसद) के अलावा कुपोषण, शुद्ध पेयजल और टीकाकरण नहीं होने के कारण पांच साल से कम उम्र के ज्यादातर बच्चों की मौत होती है. देश में करीब 30 फीसद बच्चे समय से पूर्व जन्म लेते हैं. समय पर जन्म लेने वाले बच्चों के शरीर और फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ और दुरुस्त होते हैं. वहीं समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों को श्वास संबंधी, संक्रमण और ब्रेन हैमरेज का खतरा बना रहता है, जिसके कारण वे उचित इलाज नहीं होने पर असमय दम तोड़ देते हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, देश में कुल मौतों में से दो तिहाई मौतें जन्म के पहले सप्ताह में हो जाती हैं और इनमें से दो तिहाई मौतें जन्म के दो दिन के अंदर ही हो जाती हैं. इस प्रकार 45 प्रतिशत नवजात शिशुओं की मौत 48 घंटे के अंदर ही हो जाती है.

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और अस्पताल के दूर होने के कारण समय पर गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए नहीं पहुंच पाती हैं. वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी अकुशल दाइयां ही शिशुओं का प्रसव कराती हैं, जिसके कारण जच्चा-बच्चा दोनों की जान पर खतरा बना रहता है. अशिक्षा या यों कहें कि चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में अब भी ग्रामीण महिलाएं प्रसव के लिए अकुशल दाइयों पर ही निर्भर हैं. जबकि बाल मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी है कि शिशुओं को जन्म के बाद एक-दो दिन तक अस्पताल के नियो वार्ड में रखा जाए. यहां नवजात शिशुओं को नर्स की निगरानी में किसी भी बाह्य संक्रमण से बचाकर शिशु कक्ष में रखा जाता है और उनकी उचित देख-रेख की जाती है. शिशुओं से जुड़ी अधिकतर समस्याएं प्रसव पूर्व अवधि, प्रसव के दौरान व जन्म के तुरंत बाद अपर्याप्त देख-रेख के कारण पैदा होती हैं. इसके अलावा जन्म के समय शिशु के कम भार का होना व कुपोषण के कारण बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है. सरकार ने ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को कुछ समय तक ऐसे इलाकों में कार्य करने के निर्देश तो दिए, लेकिन आज भी कोई डॉक्टर पिछड़े इलाकों में जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है.

2016 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत में 38.7 फीसद बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. भूख से पीड़ित 118 देशों में भारत का स्थान 97वां है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक भारत समेत 45 देशों में भुखमरी की स्थिति बहुत विकट हो जाएगी. यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट गोल के सलाहकार एनके सक्सेना कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है. यहां गलत योजनाओं व पैसे की कमी से नहीं, बल्कि योजनाओं का उचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने या योजनाओं के गलत डिजायन के कारण हम अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं. यही वजह है कि केन्या व बांग्लादेश जैसे देश हमसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए अक्सर गलत जानकारी देते हैं. मध्यप्रदेश में सरकार दावा करती है कि यहां केवल 1.9 प्रतिशत बच्चे ही गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जबकि यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यहां 12 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं. गलत डाटा आने के कारण सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में समस्या आती है. यही स्थिति लगभग हर राज्य में है. वहीं, आदिवासी बच्चों की मौत पर संज्ञान लेते हुए हाल में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में 500-600 बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है. क्या आपको ऐसा लगता है कि बड़ी जनसंख्या वाले देश में कुपोषण से कुछ लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहीं आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में कमी के कारण आदिवासी छात्रों की मौत हुई है. यह स्थिति तब है, जब सरकार आदिवासी छात्रों पर भारी-भरकम राशि खर्च करती है और महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लिए 552 आवासीय स्कूल चलाती है.

हालांकि अगर 1990 से तुलना करें तो बाल मृत्यु दर में काफी सुधार हुआ है. 1990 में 1000 बच्चों में से 146 बच्चे पांच साल से ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रह पाते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 48 पर आ गया है. वहीं विकसित देशों में यह आंकड़ा 5 से भी कम है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. राकेश कुमार कहते हैं कि वर्ष 2030 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति एक हजार में 12 तक लाना है. वहीं यूनीसेफ की रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर सरकारों ने अपना रवैया नहीं बदला, तो 2030 तक दुनिया में 6.9 करोड़ बच्चों की पांच साल से कम उम्र में मौत हो सकती है. इनमें आधी से ज्यादा मौतें पांच देशों में होने की आशंका है, जिसमें भारत भी शामिल है. सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल तकरीबन ऐसी रिपोर्ट आती है, लेकिन इसे लेकर न तो हमारे नीति नियंता परेशान होते हैं और न ही इन्हें सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों में तरजीह दी जाती है. केवल लोकलुभावन कार्यक्रमों और अभियानों की घोषणा करने वाली सरकार को नौनिहालों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तभी आर्थिक विकास के साथ मानव सूचकांक के आंकड़ों में भी हम अव्वल साबित हो सकते हैं. ■

हसदेव अरण्य

वन सुरक्षा और ग्रामसभाओं के प्रस्ताव की अनदेखी

कोयला खदानों के आवंटन के ख़िलाफ़ हुए ग्रामीण

चौथी दुनिया ब्यूरो

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक का आवंटन आंध्रप्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किया है. इस आवंटन का हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन पुरजोर विरोध कर रहा है. समिति का कहना है कि वे इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे. गौरतलब है कि दिसंबर 2014 में हसदेव अरण्य की 20 ग्रामसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय कोयला मंत्रालय, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालय और केंद्रीय वन मंत्रालय को सौंपा था, जिसमें कोयला खदानों का आवंटन नहीं किए जाने और समृद्ध वन संपदा व जैव विविधता को बचाने का आह्वान किया गया था. लेकिन मोदी सरकार ने उन प्रस्तावों की अनदेखी करते हुए हसदेव क्षेत्र में 6 नए कोल ब्लॉक के आवंटन राज्य सरकारों को किए हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए संविधान में दी गई व्यवस्था पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का साफ़ तौर से उल्लंघन है.

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को सघन वन संपदा, समृद्ध वन जैव विविधता, वन्य प्राणियों का आवास और हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट होने के कारण 2009 में खनन के लिए नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था. लेकिन, इन समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए सरकार सम्पूर्ण हसदेव की वन संपदा को कॉरपोरेट मुनाफे के लिए उजाड़ने की तैयारी कर रही है. कॉरपोरेट मुनाफे के लिए केंद्र और राज्य सरकार खनिज संसाधनों की लूट के लिए खुला रास्ता तैयार कर रही है, जिसमें आदिवासी, किसान, मजदूरों का दमन और पर्यावरण को नुकसान होने की पूरी आशंका है. मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक का आवंटन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें कोयले का उत्पादन कॉमर्शियल माइनिंग अर्थात बाजार में बेचने के लिए किया जाएगा. ध्यान देने की बात है कि कोल माइन (विशेष उपबंध) कानून 2015 में ही कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कोयला खनन को मंज़ूरी दी गई थी. इससे पहला कोयला खनन केवल ज़रूरत के अनुरूप कैप्टिव माइनिंग के लिए स्वीकृत था. मदनपुर साउथ का आवंटन छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एंड यूज यानी अंत उपयोग की चिंता किए बिना केवल मुनाफे के लिए कोयला बेचा जा सकेगा.

समिति का ये भी आरोप है कि राज्य सरकारों के नाम पर कॉरपोरेट घरानों को कोल ब्लॉक सौंपे जा रहे हैं. सरकार द्वारा नीलामी की प्रक्रिया से बचते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट घरानों को कोयला खदानें दी जा रही हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान, जिसे आवंटित तो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को किया गया था, परंतु पीछे के रास्ते इसका मालिक अदानी कंपनी बन गई है. इसमें विशेष बात यह है कि इस प्रक्रिया से आवंटित खदानों को मात्र 100 रुपए प्रति टन की दर से ही राज्य सरकार को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जबकि बगल की ही नीलामी के माध्यम से आवंटित चोटिया खदान को 3025 रुपए प्रति टन से रॉयल्टी देनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में बाज़ार भाव पर बेचे हुए कोयले का पूरा मुनाफा कॉरपोरेट घरानों को ही मिलेगा. आवंटन के जरिए कोयला उत्पादन से सरकारों को राजस्व की कम प्राप्ति होनी निश्चित है. इसके बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कोल ब्लॉकों का आवंटन किया जा रहा है.

वर्तमान में देश में कोयले का उत्पादन कुल मांग से ज्यादा है. कोयला मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए 1.5 बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि बिजली उत्पादन लक्ष्य के अनुसार इस मात्रा में कोयले की जरूरत 2030 में होगी. अभी से इतना ज्यादा कोयला उत्पादन सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए किया जा रहा है, जिसमें सरकार के कुछ पसंदीदा उद्योगपति शामिल हैं.

ऐसी स्थिति में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक आवंटन से कई गंभीर सवाल उत्पन्न होते हैं. मसलन, पेसा अधिनियम 1996 तथा वनाधिकार कानून 2006 के तहत पारित प्रस्तावों का उल्लंघन क्या कानूनी व्यवस्था का खिलवाड़ और संवैधानिक अधिकारों की अवमानना नहीं है? आदिवासी हितों के लिए बने महत्वपूर्ण कानूनों की अवहेलना करने वाली मोदी सरकार किस मुंह से खुद को आदिवासी हितैषी बता सकती है? नो गो क्षेत्र की नीति को तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसकी जगह बनने वाली वायलेट – इनवायलेट नीति को अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया है? ऐसी स्थिति में समृद्ध वन संपदा वाले क्षेत्रों में कोयला ब्लॉक आवंटन किस हद तक सही है? हसदेव क्षेत्र में लगातार विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटन के माध्यम से ही क्यों ब्लॉक दिया जा रहा है और क्यों यहां नीलामी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऐसी स्थिति में अदानी कंपनी जैसे कॉरपोरेट घरानों को ही खनन कार्य क्यों सौंप दिया जाता है? इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को होने वाली हानि के खिलाफ राज्य सरकार कोई विरोध क्यों नहीं करती है और क्यों लगातार ज़रूरत से ज्यादा कोयला खनन कर पर्यावरण और आदिवासी जीवनशैली का विनाश किया जा रहा है? जाहिर है, इन सवालों का जवाब सरकार को देना है, लेकिन ये भी तय है कि इन सवालों के जवाब शायद ही मिलें. ■

झारखंड में अधिकारियों और बिचौलियों का बेजोड़ गठजोड़

घोटालों में डूबा डोभा प्रोजेक्ट

प्रशान्त शरण

राज्य की महत्वाकांक्षी डोभा निर्माण योजना भी घोटालों की भेंट चढ़ गया. गांव एवं खेतों में बने गड्ढे का फोटो अपलोड कर इसे डोभा दिखा दिया गया और अधिकारियों एवं बिचौलियों का गठजोड़ फिर एक बार सरकारी राशि हड़पने में कामयाब रहा. मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इस योजना की शुरुआत ही गलत समय पर हुई. मई, 2016 में वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने डेढ़ लाख डोभा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. मुख्यमंत्री ने तल्ख लहजे में हर हाल में डोभा निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. एक डोभा के लिए 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गयी. अधिकारियों एवं ठेकेदार मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी आगे निकल गये. कागजों में पौने दो लाख से भी अधिक डोभा का निर्माण हो गया. बरसात में बने छोटे-छोटे गड्ढों का फोटो, वेबसाईट पर अधिकारियों ने वाहवाही भी लूट ली, पर झारखण्ड में अभी तक योजनाओं का जो हाल होता रहा है, वही इस योजना का भी हुआ. अधिकारी एवं ठेकेदार तो मालामाल हो गये, पर जमीन सूखी ही रह गयी.

आनन-फानन में शुरु की गयी योजना में यह जाहिर है कि काम कैसा हुआ होगा. पहले मनरेगा से इस योजना को जोड़ा गया और यह निर्णय लिया गया कि मजदूरों से काम कराये जायेंगे. बाद में इस योजना से ग्रामीण विकास विभाग, कृषि एवं पेयजल स्वच्छता विभाग को जोड़ा गया। मजदूरों से काम नहीं कराकर जेसीबी मशीनों से डोभा की खुदाई होने लगी,

राज्य की महत्वाकांक्षी डोभा निर्माण योजना भी घोटालों की भेंट चढ़ गया. गांव एवं खेतों में बने गड्ढे का फोटो अपलोड कर इसे डोभा दिखा दिया गया और अधिकारियों एवं बिचौलियों का गठजोड़ फिर एक बार सरकारी राशि हड़पने में कामयाब रहा. मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इस योजना की शुरुआत ही गलत समय पर हुई. मई, 2016 में वर्षा जल संचयन के लिए सरकार ने डेढ़ लाख डोभा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. मुख्यमंत्री ने तल्ख लहजे में हर हाल में डोभा निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया.

परिणाम यह हुआ कि अधिकांश डोभा बेतरतीब ढंग से बने, चैड़ाई-लंबाई तो कम रहे पर मशीनों से खुदाई के कारण गहराई ज्यादा हो गयी. डोभा के चारों ओर घेराबंदी भी नहीं की गई और न ही खुदाई से निकले मिट्टी से चारों ओर ऊंची मेड़ें बनायी गयी. बरसात के दिनों में इन गड्ढों में लबालब पानी भर गये तो आसपास की आबादी नहाने एवं अन्य कामों के लिए इन तालाबों में आने लगे, सुरक्षा के कोई मानक इन डोभा में नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं घटित होने लगी. अभी तीन माह में राज्य के विभिन्न भागों में हुई घटना में तीन दर्जन से अधिक बच्चों की डूबने से दुःखद मौत हो गयी. डूबने से लगातार हो रही मौत ने सरकार को भी झकझोर कर रख दिया. विभिन्न सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरु किया और आरोप लगाये कि घोटालों के लिए जगह-जगह गड्ढा बना दिया गया, जिसके कारण आये दिन नौनिहालों की मौत हो रही है. सरकार की लगातार हो रही फजीहत के बाद सरकार ने समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन प्रकाशित कराकर लोगों से डोभा के पास नहीं जाने की अपील की, साथ ही डोभा के चारों तरफ लाल झंडा लगाने का निर्देश दिया. राज्य सरकार डोभा में डूबने से हुई मौत के लिए मुआवजा देने की भी घोषणा की और एक जान की कीमत पचास हजार आंकी गयी.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह का डोभा का निर्माण कराया ही क्यों गया, जहां कोई जा ही नहीं सकता. राज्य सरकार ने राज्य में लगातार गिर रहे जलस्तर में सुधार लाने के लिए वर्षा जल के संचयन का निर्णय लिया, इसके तहत 30 फीट लंबाई-चैड़ाई एवं दस फीट गहराई वाले डेढ़ लाख डोभा बनाने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारित किया गया. यह कहा गया कि इस डोभा के पानी से किसान खेती भी कर सकेंगे, पर अधिकांश डोभा में जमे पानी का उपयोग किसान नहीं कर पा रहे हैं, वे डर से डोभा के नजदीक नहीं जा रहे हैं, उन्हें यह डर सताता है कि कहीं फिसलन के कारण गहराई में न चले जायें.

सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् एवं वैज्ञानिक डॉ. नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि डोभा स्थल का चयन ही गलत हुआ, इसे घनी आबादी बच्चों के स्कूल से दूर बनाना चाहिए. 30 फीट चैड़ी, लंबी एवं दस फीट गहराई वाले डोभा सीढ़ीनुमा बनाये जाते हैं, साथ ही डोभा से निकली मिट्टी से चारों तरफ ऊंचे मेड़ के साथ ही झाड़ियों से इसकी घेराबंदी जरुरी है. फिसलन रोकने के लिए डोभा के किनारे घास लगानी चाहिए, बड़े पेड़ों को लगाना चाहिए, इससे हमें पर्यावरण को संतुलित करने में भी लाभ मिलता, पर डोभा निर्माण के समय कोई मानक नहीं अपनाया गया, इस पर अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण घटनाएं घट रही है.

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुण्डा का मानना है कि राज्य में भूगर्भ जलस्तर तेजी से गिर रहा है, जो चिंता का विषय था, इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनायी, इससे दो लाभ था, एक तो वर्षा का जल जो बर्बाद होता था, उसे रोका गया, साथ ही किसानों को इससे खेती करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं हो सकता है डोभा निर्माण में गड़बड़ी हुई हो, इसकी जांच करायी जायेगी.

इससे पूर्व भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने भी एक लाख तालाब बनवाने का फैसला लिया था. यह काम भी युद्ध स्तर पर शुरु हुआ, पर इस काम में जमकर घपले-घोटाले हुए. तालाब बनाने में केवल औपचारिकता ही निभाया गया. ठेकेदार एवं अधिकारियों ने बरसात में काम कराकर सरकारी राशि का गबन कर लिया था, पर पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया गया।

कुछ यही हाल इस योजना का भी हुआ है, अगर इसकी जांच करायी जाय, तो करोड़ों का घोटाला उजागर होगा और कई अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है. अब देखना है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास कौन-सा कदम उठाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

हाशिमपुरा दंगा पीड़ितों को इंसाफ का इंतज़ार है

ए.यू. आसिफ

इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि करीब 30 साल बीत जाने के बाद भी लोग हाशिमपुरा मामले में इन्साफ की बाट जोह रहे हैं. वो बदनसीब 42 लोग, जिन्हें पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेब्लरी) के जवानों ने 22 मई 1987 को दिन-दहाड़े घरों से निकाल कर मेरठ में हाशिमपुरा मोहल्ला के बाहर गुलमर्ग सिनेमा के सामने जमा किया और फिर ट्रक में बिठा कर मुरादनगर (गाज़ियाबाद) के गंग नहर और हिंडन नदी के पास लाए और गोलियों से भून कर पानी में लाशें बहा दीं. उनमें से बचे कुछ लोग और मारे गए लोगों के परिजन अब भी मुआवज़े से वंचित हैं. यह मामला गाज़ियाबाद की अदालत से चक्कर काटता हुआ जल्द मुकदमा निपटने के लिए दिल्ली की तीसहजारी अदालत में लाया गया. वहां 12 मार्च 2015 को सबूत के अभाव में कातिल का पता न लग सकने पर पीएसी के 16 आरोपी जवानों को निर्दोष करार दिया गया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह 1987 के घटना से संबंधित 22 जून 1989 की सीबी-सीआईडी की रिपोर्ट 24 नवम्बर तक अदालत में पेश करे. हाई कोर्ट ने उस रोज़ यह भी निर्देश दिया था कि 24 नवम्बर से पहले प्रतिवादी यह ज़ाहिर करते हुए हलफनामा दाखिल करें कि पूरे मामले से संबंधित रिकार्ड्स के रख-रखाव, संरक्षण और ख़त्म करने के लिहाज़ से कब और क्या क़दम उठाये गए?

इसमें दिलचस्प बात यह थी कि जो घटना दुनिया भर में क्रूरता और बर्बरता का निशान बन गई और जिसके नतीजे में बदनसीब 42 लोगों में से अधिकतर की मौत हो गई, उसे अंजाम देने वालों का अदालत पता नहीं लगा सकी. वाकई यह कैसी अजीब बात है कि कोई सबूत नहीं मिल सका जबकि इस संबंध में कई जांच समितियां बिठाई गईं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुल कर पीएसी के कई जवानों पर शक की सुई रखी थी.

21 मार्च 2015 को दिल्ली की निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उन 42 अभागे लोगों में से जिन्दा बचे जुल्फिकार नासिर ने चश्मदीद गवाह के तौर पर इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. ये वही जुल्फिकार नासिर हैं, जिन्होंने पीएसी के जवानों की मुरादनगर में गंग नहर पुल के पास गोलियां खाकर लंगड़ाते हुए किसी तरह नहर के किनारे-किनारे चल कर ट्रक तक आने की हिम्मत की और मशहूर कुल्फी फालूदा की दूकान के आगे थाना के सामने एक पेशाब घर में पनाह ली. उन्होंने किसी तरह इस गोलीबारी में अपनी जान बचाई और बाद में इस घटना के चश्मदीद गवाह बन गए. अफ़सोस कि आज उन्हें फर्स्ट ऐड देने वाले डॉ. खालिद हाश्मी और उनके पिता हकीम जाकिर हुसैन इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन उनका बचाया हुआ यह शख्स असल हत्यारों के लिए सबसे बड़ा मसाला बना हुआ है.

इन्साफ की इस लड़ाई में जुल्फिकार नासिर अकेले नहीं हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में तीसहजारी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, उनमें उस ज़माने के लोक दल और अब भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी शामिल हैं. डॉ. स्वामी हाशिमपुरा मामले से शुरू से ही जुड़े रहे हैं. इस घटना के फ़ौरन बाद वो पूर्व कानून उपमंत्री और वरिष्ठ राजनेता मुहम्मद यूनुस सलीम के साथ मुरादनगर की गंग नहर और गाज़ियाबाद की हिंडन नदी के पास गए थे और हिंडन नदी में बहती कुछ लाशों को भी देखा था. उन्होंने उसी जगह लाशों के पास खड़े होकर अंग्रेजी साप्ताहिक रेडिएंस को इंटरव्यू दिया था और उस घटना को राज्य प्रायोजित नरसंहार करार दिया था. उनके इसी

इंटरव्यू के बाद इस घटना को इस नाम से जाना जाने लगा और आज भी इसी नाम से जाना जाता है.

यह पत्रकार भी उस सफ़र में उनके साथ था और उपरोक्त इंटरव्यू भी उसी ने लिया था. इस पत्रकार को अभी तक यह बात याद है कि सड़ी हुई लाश से आ रही बदबू को बर्दाश्त न करने के कारण डॉ. स्वामी ने अपनी धोती के एक सिरे से अपनी नाक ढंक ली थी. मुहम्मद यूनुस सलीम ने भी अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था और इस पत्रकार से कहा था कि दूर खेत में चल कर बात करें, क्योंकि बदबू की वजह से यहां खड़ा होना मुश्किल है. तब इस पत्रकार का एकदम से जवाब था कि इसी जगह इंटरव्यू होगा, ताकि वास्तविक प्रतिक्रिया सामने आ सके. रेडिएंस मैगज़ीन में नाक पर रुमाल रखे छपा यह इंटरव्यू आज भी अपनी कहानी आप कह रहा है. डॉ. स्वामी ने एक साल बाद इस त्रासदी की बरसी पर मुरादनगर से राजघाट दिल्ली तक पैदल मार्च किया था. इस मार्च में सैकड़ों लोग उनके साथ थे. इसके बाद उन्होंने बोट क्लब पर आमरण अनशन किया, ताकि इस मामले में इन्साफ हो सके. केंद्र सरकार द्वारा यकीन दिलाने के बाद उन्होंने अपन अनशन समाप्त किया था. इस अनशन के बाद भी डॉ. स्वामी इस त्रासदी को लेकर आवाज़ उठाते रहे. वे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम का इस घटना में हाथ होने का इलज़ाम लगाते रहे हैं.

इस तरह जुल्फिकार नासिर के साथ डॉ. स्वामी की भी इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह 1987 के घटना से संबंधित 22 जून 1989 की सीबी-सीआईडी की रिपोर्ट 24 नवम्बर तक अदालत में पेश करे. हाई कोर्ट ने उस रोज़ यह भी निर्देश दिया था कि 24 नवम्बर से पहले प्रतिवादी यह ज़ाहिर करते हुए हलफनामा दाखिल करें कि पूरे मामले से संबंधित रिकार्ड्स के रख-रखाव, संरक्षण और ख़त्म करने के लिहाज़ से कब और क्या क़दम उठाये गए? इस संबंध में उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जेनरल ज़फरयाब जिलानी ने इस पत्रकार से फोन पर बात करते हुए कहा कि इस मामले में दो गवाहों को तलब किया गया है. उन्होंने यह भी कहा की सीबी-सीआईडी की 1989 की उपरोक्त रिपोर्ट भी मिल गई है और मुकदमे की मज़बूत पैरवी के लिए काफी सबूत अब उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित ट्रक की पहचान न होना एक बड़ी भूल रही है.

वैसे हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर को इस बात पर गहरी चिंता ज़ाहिर की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक सभी पीड़ितों के परिवार को उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा नहीं दिया है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अनुग्रह राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है. जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पीएस तेजी की खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला 1987 में शुरू हुआ और इसके लिए सभी पीड़ितों को स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा अभी तक नहीं मिला है. लिहाज़ा यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास इस मामले में उन पीड़ितों की सूची और पूरी जानकारी पेश करे जिन्हें मुआवजा दिया गया है. दरअसल मेरठ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव की यह ज़िम्मेदारी है कि वह राहत के हक़दार लोगों के पहचान की प्रक्रिया को पूरा करे और इस बात को देखे कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत अनुग्रह राशि पीड़ितों के परिवारों तक पहुंचे. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी ताकीद की कि पीड़ितों और उनके परिजनों के पहचान की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से लेकर 6 हफ़्तों के अंदर पूरा हो जाए और मुआवजे की रक़म हर हाल में उसके 15 दिनों के अंदर अदा कर दी जाए.

बहरहाल अब देखना यह है कि दिल्ली की तीस हजारी अदालत हाशिमपुरा मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आखिरी फैसला नहीं कर पाई थी, अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला देता है. इस बड़े फैसले का इंतज़ार सिर्फ जुल्फिकार नासिर, डॉ. स्वामी और नेशनल ह्यूमन राइटस कमीशन को ही नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ की उम्मीद रखने वाले देश के सभी नागरिकों को भी है.■

feedback@chauthiduniya.com

मणिपुर विश्वविद्यालय आरक्षण मुद्दा

आदिवासियों का हक छीनने का कुचक्र

एस. बिजेन सिंह

देश के अन्य हिस्सों की तरह आरक्षण का मुद्दा अब पूर्वोत्तर भारत में भी उठने लगा है. हाल में मणिपुर विश्वविद्यालय में आरक्षण को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी है. उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय के रिक्रिएशन हॉल, तीन डीटीपी हॉल और कैंटीन को जला दिया है. मणिपुर विश्वविद्यालय ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की मांग है कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नॉर्म्स द सेंट्रल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एमेंडमेंट एक्ट 2012 लागू हों. राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार एसटी को 31 प्रतिशत, एससी को 2 प्रतिशत और ओबीसी को 17 प्रतिशत आरक्षण मिला है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मणिपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है, इसलिए यूजीसी के आरक्षण नॉर्म्स द सेंट्रल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट 2006 के हिसाब से होने चाहिए. यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार, एसटी को 7.5 प्रतिशत, एससी को 15 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है. प्रशासन के इस निर्णय को लेकर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. यूनिवर्सिटी का नया सत्र इस विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया. नया सत्र जून में शुरू होना था, जो अब तक शुरू नहीं हो सका है. यहां तक कि पिछली परीक्षाओं का परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है.

पुलिस प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को जलाने के मामले में 18 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. इसके बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पकड़े गए छात्रों को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग कर रही है. वहीं विश्वविद्यालय में आगजनी की घटना के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इन चार्ज प्रोफेसर एम धनेश्वर ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस्तीफा सौंप दिया है. प्रोफेसर धनेश्वर को पूर्व वाइस चांसलर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ समय के लिए प्रभार सौंपा गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में अशांत माहौल व शैक्षणिक वातावरण में सुधार नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा.

गौरतलब है कि मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 5 जून 1980 को हुई थी. तबसे विश्वविद्यालय में नामांकन व टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ की नौकरी में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नॉर्म्स ही चले आ रहे थे. 13 अक्टूबर 2005 को मणिपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद से यानी 2006-07 के सत्र से यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स शुरू होना था. फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ समय तक राज्य सरकार के आरक्षण नॉर्म्स का ही पालन करता रहा. दो साल गुजर जाने के बाद 2008-09 में यहां सेंट्रल का आरक्षण नॉर्म्स चलाना शुरू किया गया था. इसी समय से ट्राइबल स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू किया था, जो अबतक जारी है. फिर 2012 में बिल एमेंडमेंड हुआ. द सेंट्रल एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एमेंडमेंट एक्ट 2012 को 2012 से लेकर 2015 तक विश्वविद्यालय में चलाया जा चुका है. ट्राइबल स्टूडेंट्स ने इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण ली. इस मामले में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह सुझाव दिया कि दोनों एक्ट में से जो उचित लगे, उसे चलाया जाए. इसके बाद विवि प्रशासन ने 4 अप्रैल 2016 को ऐलान किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स ही फिर से विश्वविद्यालय के 2016-2017 एडमिशन में लागू होंगे. इस निर्णय से नाखुश मणिपुर यूनिवर्सिटी ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बोस्को जायचे खरम ने कहा कि जो आरक्षण के नियम चलाए जा रहे थे, उसे छोड़कर दूसरा नियम तत्काल लागू करना छात्रों को मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि हम लोग जो चीज नहीं है, उसकी मांग नहीं कर रहे हैं. जो नियम था, उसी को बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग केवल ग्रुप सी और डी में ही इस नियम को लागू करवाने की है. 23 मार्च 2016 को यूजीसी की तरफ से एक सख्त निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए गए थे. इसके कुछ दिनों बाद रिजर्वेशन के नियम बदल देना ट्राइबल स्टूडेंट्स की उपेक्षा करना है. खरम ने कहा कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकर भी छात्रों को उनका उचित हक नहीं मिल रहा है, तो राज्य के विवि रहना ही ज्यादा अच्छा है. उन्होंने कहा कि 2012 के एमेंडमेंड बिल लागू होने के बावजूद ट्राइबल स्टूडेंट्स की उपेक्षा होती रही. ऐसे में 2006 वाला कानून अगर लागू होगा, तो हम लोगों के यहां पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है. इसलिए ट्राइबल छात्रों ने विश्वविद्यालय का छात्रावास 10 अक्टूबर को छोड़ दिया. जो बाकी छात्र बचे रह गए उन्होंने भी कक्षा के बहिष्कार करने का एलान किया. मुस्पू (मणिपुर ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन) ने चेतावनी दी है कि विवि प्रशासन ने अगर अपने निर्णय वापस नहीं लिए तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे.

दूसरी तरफ, मुसु (मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन) के अध्यक्ष ओइनाम प्रेमसागर ने मांग की है कि विवि में अशांति के माहौल को तत्काल खत्म किया जाए. साथ में यह भी मांग की कि जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, उसे जल्द चालू कराकर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए. मुसु छात्रों की एक सामूहिक संस्था है, जिसमें ट्राइबल छात्र (ईसाई धर्म मानने वाले), हिंदू (जो जनरल कैटेगरी के हैं) एवं मुसलमान छात्र भी शामिल हैं. लेकिन मुत्सु (मणिपुर ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन) केवल ट्राइबल छात्रों का संगठन है, जो एसटी में आता है.

मणिपुर यूनिवर्सिटी का आरक्षण मुद्दा ट्राइबल और घाटी में रह रहे सभी जातियों (हिंदू, मुसलमान व मैतै), जो एससी और ओबीसी हैं, के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है. राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार, मणिपुर की 25 लाख आबादी में से करीब 9 लाख ट्राइबल्स हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जबकि बाकी हिस्से के लोग घाटी में. मणिपुर में पहले भी पहाड़ बनाम घाटी का विवाद चलता रहा है. एक सवाल यह भी उठ रहा है कि शहर के कुछ हिस्सों को छोड़कर, बाकी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मैतै समुदाय के लोग गरीब और पिछड़े हैं. वे अधिकतर ओबीसी में आते हैं. ऐसे में अगर 2006 का कानून विवि में अगर लागू नहीं होगा, तो ट्राइबल स्टूडेंट्स के अलावा बाकी समुदाय के छात्र भी आंदोलन कर सकते हैं. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात की चिंता सता रही है कि छात्रों के इस विरोध-प्रदर्शन के चक्कर में कहीं यूजीसी ग्रांट न बंद हो जाए. अगर समय रहते विश्वविद्यालय प्रशासन व छात्र संगठनों के बीच विवाद को नहीं सुलझा लिया गया, तब आने वाले समय में जातीय व सांप्रदायिक टकराव का रूप ले सकता है. इस मुद्दे पर यूजीसी और राज्य सरकार को पहल कर विश्वविद्यालय में आरक्षण मुद्दे का समाधान निकाल लेना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव सामने, पर उत्तर प्रदेश में सारे राजनीतिक दल दिशाहीन

कलह और कलुष के दलदल में सभी दल

सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने, सपाई कार्यकर्ताओं की राज्य में चल रही गुंडागर्दी तथा जमीन कब्जाने की घटनाएं सरकार की छवि को प्रभावित कर रही हैं तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार विकास के दावे के साथ ही सभी चुनावी वादे पूरे करने की भी घोषणा कर रहे हैं. साढ़े चार वर्ष की सरकार में अखिलेश सरकार कानून-व्यवस्था और गुंडागर्दी के आरोपों से मुक्त नहीं हो पाए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं. लेकिन अभी तक राज्य में सरकार बनाने के दावेदार सभी राजनीतिक दल चुनाव एजेंडे और जनसमस्याओं को लेकर दिशाहीन है. कानून व्यवस्था सुधारने और विकास के दावे अवश्य राजनीतिक रैलियों में किये जा रहे हैं परन्तु राजनेताओं के इन दावों में सच्चाई का पुट तक नहीं है. यही वजह है कि नेताओं के भाषणों में जनता को प्रभावित करने वाले शब्दों का जोर नहीं है. कुछ देर तक उपहार बांटने तथा कर्ज माफी आदि तरह-तरह के लुभावने वादे करने में भी जुटे हैं लेकिन इनके वादों पर जनता का भरोसा नहीं जम पा रहा है. चुनावी वादों से सभी दल राज्य के चुनावी गणित को देखते हुए जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं. प्रदेश में दर्जनों राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बाद भी केवल चार ही दल सत्ता संघर्ष में चल रहे हैं. फिलहाल चुनावी संग्राम में इन दलों की स्थिति देखने लायक है.

सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने, सपाई कार्यकर्ताओं की राज्य में चल रही गुंडागर्दी तथा जमीन कब्जाने की घटनाएं सरकार की छवि को प्रभावित कर रही हैं तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार विकास के दावे के साथ ही सभी चुनावी वादे पूरे करने की भी घोषणा कर रहे हैं. साढ़े चार वर्ष की सरकार में अखिलेश सरकार कानून-व्यवस्था और गुंडागर्दी के आरोपों से मुक्त नहीं हो पाए. अखिलेश सरकार पर यह आरोप विपक्ष से ज्यादा उनके पिता तथा सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ज्यादातर सार्वजनिक सभाओं में करते रहे. मुलायम सिंह प्रदेश की राजनीति के वह नेता हैं जिनकी सरकार के खिलाफ 2007 में खराब कानून-व्यवस्था के आरोपों से ही बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के चुनावी वादे पूरे करने के जो भी वादे करें लेकिन कई महत्वपूर्ण वादों को शायद वह भूल ही गए. पहले मुलायम सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की और 2012 के चुनाव में यह भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का वादा किया गया जिसका चुनाव में लुभावना असर हुआ, परन्तु सरकार बनने के बाद सपा सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए. छात्रों को लैपटॉप और आईपैड देने का वादा भी आधा-अधूरा ही रहा. इसी प्रकार बेसिक छात्रों को मुफ्त किताबें और ड्रेस देने का हर वर्ष का वादा अभी तक कभी पूरा ही नहीं हुआ.

अखिलेश सरकार के चार साल के शासन में हुआ, वह यादव कुल के जवानों को सरकारी नौकरी में किसी भी तरह से पहुंचाने का प्रयास सफल रहा. इसके लिए भर्ती करने वाली सारी संवैधानिक संस्थाओं का क्रियाकलाप भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. इसके साथ ही सभी कमाऊ पदों तथा पुलिस थानों पर यादव कुल के लोगों को ही प्रमुख जिम्मेदारी दी गई. मुस्लिम हितों के संरक्षण की बात अवश्य की गई परन्तु कानून-व्यवस्था और दंगों के मामलों में ही उनके अपराधिक तत्वों को संरक्षण दिया गया. शिक्षा तथा रोजगार के लिए कोई पहल नहीं की गई.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार विकास के वादे करते रहे, जिसमें लखनऊ मेट्रो उनकी उपलब्धि रही परन्तु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस के पीछे की कहानी कुछ और ही कहती है. प्रदेश में तमाम दावों के बाद भी सड़कों और नहरों की हालत अत्यन्त खराब है. इन तमाम ऊंच-नीच के बीच चुनाव से कुछ माह पूर्व सैफई के यादव कुल में सत्ता को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है. यदुवंश एकता का जो भी दावा करे परन्तु इस घटना ने सपा के राजनीतिक भविष्य की पटकथा लिख दी है. यह संघर्ष और बढ़ने के ही आसार हैं. चुनाव बाद ही इसका पटाक्षेप होने की संभावना है. ऐसे में सपा के पास भी यादव समर्थकों के अलावा मुस्लिमों के ही साथ का विश्वास है. नौकरियों में यादवों को जिस प्रकार तरजीह दी गई है तथा अन्य वर्गों के योग्य छात्रों की उपेक्षा की गई है, उसका सपा सरकार के खिलाफ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. अखिलेश सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को स्मार्ट फोन देने का भी वादा किया है, परन्तु बेरोजगारी भत्ता तथा लैपटॉप से वंचित युवा किसान इस वादे पर कितना विश्वास करेगा, यह समय बताएगा.

बहुजन समाज पार्टी वर्ष- 2007 में सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के नारे के साथ राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी. इसके पीछे तत्कालीन मुलायम सरकार में खराब कानून-व्यवस्था को लेकर जनता के आक्रोश का भी प्रभाव रहा. उस समय तक भाजपा तथा कांग्रेस विपक्षी दल सपा का पुरजोर विरोध करने में अपना पक्ष नहीं रख सके और बसपा की आक्रामक नीति ने जनता के विश्वास को अपने पक्ष में कर लिया. मुख्यमंत्री मायावती के 5 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार और सर्वजन हितों को छोड़कर हर हाल में निजी हितों को साधने की प्रवृत्ति ने जनता के बीच बसपा के मूल चरित्र का पर्दाफाश कर दिया. वर्ष 2012 में चुनाव हारने के बाद भी बसपा मुखिया द्वारा सांसदों, विधायकों तथा अन्य पार्टी पदाधिकारियों से चल रही वसूली की चर्चाओं ने पार्टी में आक्रोश पैदा कर दिया. लोकसभा चुनाव में इसका बसपा के खिलाफ माहौल बना जिससे पार्टी का एक भी सांसद जीत नहीं सका. लगातार धन उगाही से परेशान पार्टी के कई बड़े नेता दल छोड़ गए. हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब बसपा के समर्थन में दलितों के साथ अन्य वर्गों का समर्थन हासिल नहीं हो पा रहा है. मायावती ने मुसलमानों को लुभाने के लिए 130 से ज्यादा सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है. अब दलित-मुस्लिम गठबंधन ही बसपा का भविष्य तय करेगा.

भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में नरेन्द्र मोदी की बहुमत की सरकार बनने के बाद से अपना पलड़ा भारी मान कर चल रही है परन्तु जनता को तमाम मुद्दों पर जिस प्रकार अपेक्षा थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है. भ्रष्टाचार कम हुआ है, परन्तु महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है. ढाई वर्ष के मोदी सरकार के कामकाज से भाजपा कार्यकर्ता दुखी हैं और सरकार से संगठन स्तर पर वह उपेक्षित महसूस कर रहा है. मंत्री से पार्टी के नेता तक कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते. भाजपा संगठन अब राजनीतिक दल से ज्यादा मैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया है. अब पैसे और मैनेजमेंट से बड़ी सभाएं कर भाजपा नेता गदगद हो रहे हैं. वोटर लिस्ट से कागजी बूथ लिस्ट तैयार कर पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं से अपनी पीठ ठुकवा रहे हैं. पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं की बाढ़ से भाजपा कार्यकर्ता दुखी हैं और इनके साथ सामन्जस्य बैठाना संभव नहीं लगता. ऐसे में पार्टी को चुनाव के समय प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है. प्रदेश में भाजपा के खिलाफ यादव और मुस्लिम मतदाता एकतरफा खिलाफ है. भाजपा के लिए अनुकूल यह है कि दलित-यादव को छोड़ ज्यादातर सवर्ण एवं पिछड़ी जातियां उसके समर्थन में खड़ी हैं. भाजपा के पक्ष में रहने के लिए इन वर्गों के सामने विकल्प हीनता भी है, जिनका सपा एवं बसपा में अपना हित सधता नहीं दिख रहा है. प्रदेश में भाजपा का कोई सर्वमान्य नेता भी नहीं है. इसके कारण विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मोदी के नाम का ही सहारा है. यह मोदी मंत्र बिहार एवं दिल्ली में फेल हो चुका है. ऐसे में सही चुनावी रणनीति नहीं अपनाई गई और प्रत्याशी चयन में भाई-भतीजावाद होने पर पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. इसके लिए कांग्रेस ने अपने राजनीतिक सिपहसालारों पर विश्वास न कर पॉलिटिक्स इवेन्ट मैनेजर के रूप में उभरे प्रशान्त किशोर की सेवाएं ली हैं. प्रदेश की चुनावी तैयारियों के लिए कांग्रेस ने भी जातीय समीकरण आजमाया है परन्तु पहले फेज में ही इसकी कलई खुल गई है. फिल्मी दुनिया के राज बब्बर को कांग्रेस ने जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास अब कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है. यही नहीं दिल्ली से लाकर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया जो उम्र एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से चार दशक पीछे चली गई हैं. ऐसे चेहरों के बल पर कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, यह तो समय बताएगा परन्तु यह साफ है कि इनके नाम से जातीय वोट कांग्रेस को मिलना मुश्किल होगा. चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट पंचायत चली. यह खाट पंचायत पश्चिम की देन है, परन्तु इसे पूरब, मध्य एवं बुन्देलखंड में भी आजमाया जा रहा है. इस पंचायत के नाम से चल रही राहुल की यात्रा में राज्य विधानसभा चुनाव की झलक ही नहीं मिल रही है. पूरा भाषण केन्द्र एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध पर टिका है. इससे यह जन प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव न लड़कर अगले 2019 के लोक सभा चुनाव की तैयारी कर रही है.

प्रदेश में इन चार प्रमुख दलों की चल रही चुनावी तैयारियों एवं राजनीतिक स्थितियों से साफ है कि अभी तक किसी के भी पक्ष की हवा खुलकर नहीं चल रही है. हालांकि चुनावी समीकरणों से यह तो साफ है कि इस बार छोटे दलों की भूमिका वोट काटने की नहीं होगी और चुनाव तक जनता पूर्ण बहुमत की सरकार का मन बना लेगी. इसमें जो भी दल पिछड़ेगा, वह बहुत पीछे हो जाएगा. ऐसे में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति की ठोस कार्रवाई करनी होगी. राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों पर भी जनता को विश्वास दिलाना होगा. ■

भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में नरेन्द्र मोदी की बहुमत की सरकार बनने के बाद से अपना पलड़ा भारी मान कर चल रही है परन्तु जनता को तमाम मुद्दों पर जिस प्रकार अपेक्षा थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है. भ्रष्टाचार कम हुआ है, परन्तु महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है. ढाई वर्ष के मोदी सरकार के कामकाज से भाजपा कार्यकर्ता दुखी हैं और सरकार से संगठन स्तर पर वह उपेक्षित महसूस कर रहा है. मंत्री से पार्टी के नेता तक कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते. भाजपा संगठन अब राजनीतिक दल से ज्यादा मैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया है. अब पैसे और मैनेजमेंट से बड़ी सभाएं कर भाजपा नेता गदगद हो रहे हैं. वोटर लिस्ट से कागजी बूथ लिस्ट तैयार कर पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं से अपनी पीठ ठुकवा रहे हैं. पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं की बाढ़ से भाजपा कार्यकर्ता दुखी हैं और इनके साथ सामन्जस्य बैठाना संभव नहीं लगता.

feedback@chauthiduniya.com

शहाबुद्दीन को लेकर लालू कठघरे में

इर्शादुल हक

शहाबुद्दीन तीन सप्ताह के लिए बाहर आया, फिर जेल की उन्हीं सलाखों के पीछे चले गया, जहां वह कमोबेश 11 वर्षों से थे. इन तीन सप्ताह तक वह मीडिया, अदालत और समाज के हर वर्ग की चर्चा का केंद्रीय विषय बने रहे. यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समाज का एक वर्ग उनका जबर्दस्त विरोधी है. यह वर्ग उनके अपराध, बाहुबली की छवि और हत्या का सजायाफ्ता मुजरिम होने के आधार पर उनका विरोधी है. लेकिन शहाबुद्दीन की पहचान सिर्फ यही मान लेना उनकी हैसियत को कम करने जैसा है, क्योंकि इसी समाज का एक बड़ा वर्ग उनका समर्थक है. यह वर्ग शहाबुद्दीन के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर सकता है. तमाम कुतर्क गढ़कर यह साबित कर सकता है कि शहाबुद्दीन उस वर्ग के हीरो हैं. 30 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्होंने बिना देर किए खुद को अदालत के हवाले कर दिया, तो उसके बाद उनके समर्थकों में उनके प्रति सहानुभूति अपने चरम पर पहुंच गई. नतीजा यह हुआ कि एक अक्टूबर से उनके समर्थक सड़कों पर आने लगे. पहले गोपालगंज, गया और फिर सीवान और इतना ही नहीं दिल्ली के जंतर-मंतर तक उनके समर्थक सड़कों पर कूद पड़े. गया में अनेक जिला पार्षदों के नेतृत्व में लोग सड़क पर आ गए, तो गोपालगंज में कैंडिल मार्च में लोगों ने उतर कर उनके प्रति समर्थन और सहानुभूति जताई. लेकिन 3 अक्टूबर को आयोजित सीवान का प्रदर्शन तो मिसाल कायम कर गया. हालत यह हो गई कि 8-घंटे तक सीवान शहर उनके समर्थकों से जाम हो गया. 15-20 हजार लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें नीतीश कुमार पर जम कर निशाना तो साधा ही गया, साथ ही लालू प्रसाद के खिलाफ भी आवाजें उठीं. शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमुख साजिशकर्ता घोषित किया गया, तो लालू प्रसाद पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने शहाबुद्दीन के प्रति उदासीन रवैया अपनाया और इसी कारण उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा. औपचारिक रूप से इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल तो शामिल नहीं था, लेकिन सीवान और गोपालगंज के अधिकतर राजद नेता और सक्रिय कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने. इनमें कुछ वर्तमान व पूर्व विधायक, वर्तमान व पूर्व जिला पार्षद और राजद के स्थानीय पदाधिकारी तक शामिल थे. इस प्रदर्शन की अध्यक्षता सीवान जिला राजद के अध्यक्ष परमात्मा राम ने खुद की.

2015 में विधानसभा चुनाव जीत कर सत्ता संभालने के बाद यह पहला अवसर था, जब राजद को अपने संगठन के अंदर इतनी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ा. हालात यह है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस मामले में सार्वजनिक तौर पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं. दूसरी पीढ़ी के नेताओं की तो बात ही छोड़िए. इन पंक्तियों के लेखक के सामने इस मामले में राजद के एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार ने माना कि शहाबुद्दीन प्रकरण पार्टी के लिए गंभीर चिंता की बात है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शहाबुद्दीन का प्रभाव सीवान और गोपालगंज में तो है ही, इसलिए लालूजी चुप हैं. बोलें भी तो क्या.

अगर किसी दल के अंदर नाराजगी और विरोध के स्वर इतनी मजबूती से उठें तो सैद्धांतिक रूप से आलाकमान इस पर कार्रवाई तक कर देता है. लेकिन शहाबुद्दीन मामले में आलाकमान चुपी साधे हैं. खास कर तब जब सरकार गठबंधन

की हो और विरोध-प्रदर्शनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शहाबुद्दीन को जेल भेजने में सीधा साजिशकर्ता घोषित किया जा रहा हो, साथ ही दबी जुबान में लालू प्रसाद पर भी सवाल उठाए जा रहे हों. इस पूरे मामले में विश्लेषक यह मान रहे हैं कि लालू प्रसाद को अंदाजा है कि शहाबुद्दीन समर्थकों का यह उबाल उनके समर्थकों के अलावा मुसलमानों के एक बड़े वर्ग तक पहुंच चुका है. मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में यह परसेप्शन पेवस्त हो चुका है कि हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद जब प्रशांत भूषण, चंदा बाबू (जिनके बेटे की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है) के लिए बतौर वकील जमानत खारिज कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये तो लगे हाथों बिहार सरकार भी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई? शहाबुद्दीन समर्थकों के गुस्से का कारण यही है कि ऐसे में लालू प्रसाद ने इस मामले में नीतीश कुमार से विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया. इस वर्ग की नाराजगी का एक तर्क यह भी है कि शहाबुद्दीन का बचाव करने के लिए राजद सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अपना हाथ क्यों पीछे खींच लिया? ध्यान रहे कि मीडिया में पहले यह खबर आ चुकी थी कि राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन का बचाव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 30 सितम्बर के बाद सोशल मीडिया पर शहाबुद्दीन समर्थकों की गठबंधन सरकार के खिलाफ नाराजगी चरम पर है. जमीलुद्दीन जिदान खान ने इस मामले में लंबा पोस्ट डालते हुए लिखा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर राजद और जद यू मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं और यह भी लिखा कि शहाबुद्दीन को इसलिए जेल जाने दिया गया क्योंकि वह मुसलमान हैं, जबकि समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव में आतंकी हमले में 68 से ज्यादा लोगों की हत्या के आरोपी व संघ प्रचारक असीमानंद को जमानत मिल गई तो उनकी जमानत के खिलाफ न तो नीतीश कुमार ने एक लफ्ज कहा और न ही लालू प्रसाद ने.

शहाबुद्दीन समर्थकों की सोशल मीडिया पर इस आक्रामकता को जाहिर तौर पर राजद के सोशल मीडिया सेल के रणनीतिकार बड़ी बारीकी से देख रहे हैं. लेकिन इस मामले में उसकी तरफ से भी कोई औपचारिक पोस्ट नहीं आया है. हां, पिछले दिनों राजद से सहानुभूति रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक पोस्ट लिखा और सफाई दी कि अकलियत समाज के भाइयों को यह समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव पिछले 25 वर्षों से जननायक के तौर पर स्थापित हैं और उनके खिलाफ हमेशा मीडिया ट्रायल चलता है और उन्हें खुद अदालत के चक्कर में विरोधियों ने फंसा रखा है, जबकि वे निर्दोष हैं. इसके बावजूद वे अपने लिए कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हैं. हालत यह है कि अब वह चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं. ऐसे में अकलियत समाज के लोगों को समझना चाहिए कि शहाबुद्दीन से जुड़े अदालती मामले में लालूजी कैसे कुछ कर सकते हैं? जब इस पोस्ट को फेसबुक पर किसी ने शेयर किया तो इसे राजद से सहानुभूति रखने वाले कई लोगों ने कॉपी कर दोबारा अपने-अपने टाइमलाइन पर पेस्ट किया और यह बताने की कोशिश की कि यह अदालती मामला है और इसलिए इस मामले में राजद या लालू प्रसाद पर आरोप लगाना सही नहीं है. इस पोस्ट में लिखे गये शब्द से यह आभास तो होता ही है कि राजद शहाबुद्दीन मामले में सफाई देने और खुद को बचाने की मुद्रा में है.

उधर राजद के अंदर शहाबुद्दीन के ऊंचे कद से कोई इसलिए भी इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कुछ महीने पहले जब राजद का संगठनात्मक चुनाव हुआ और लालू प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, तब जेल में रहने के बावजूद शहाबुद्दीन को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य खुद लालू प्रसाद ने बनाया था. दूसरी तरफ जेल से बाहर आने और फिर जेल में वापस पहुंच जाने के बाद बिहार के मुसलमानों के एक वर्ग में शहाबुद्दीन के प्रति जबर्दस्त सहानुभूति उमड़ी है, जबकि इसके बरक्स इस वर्ग में लालू के प्रति नाराजगी भी बढ़ी है. इसका आभास लालू प्रसाद को निश्चित तौर पर है. देखने की बात है कि आने वाले दिनों में वे इसकी भरपाई कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल तो यह तय है कि शहाबुद्दीन प्रकरण में राष्ट्रीय जनता दल गंभीर उलझन में है. एक तरफ वह खुल कर शहाबुद्दीन समर्थकों से कुछ कह नहीं पा रहा तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर यह परसेप्शन भी विकसित हुआ कि जद यू ने शहाबुद्दीन को सबक सिखाने की ठान ली, लेकिन राजद कुछ नहीं कर सका. यहां यह ध्यान देने की बात है कि जब 10 सितम्बर को शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार को 'परिस्थितियों का नेता' बताया था, तो इसके दूसरे ही दिन जद यू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शहाबुद्दीन को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की धमकी देते हुए यहां तक कह दिया था कि राज्य सरकार ऐसी सुई चुभोती है जिसके दर्द का एहसास तत्काल नहीं होता. नीरज के इस बयान में सबक सिखाने की भावना शहाबुद्दीन समर्थकों ने महसूस की थी.

शहाबुद्दीन मामले में राजद और जद यू के बीच टकराव की स्थिति बन गई है, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तो तय है कि दोनों दलों के बीच इस मामले में अंदर ही अंदर शीतयुद्ध जैसे हालात जरूर हैं. हालांकि इसका मतलब यह भी कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस शीतयुद्ध का कोई असर गठबंधन की सेहत पर पड़ेगा. लेकिन साथ ही इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में गठबंधन में सहमात का खेल नहीं बढ़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

Government of Madhya Pradesh

MADHYA PRADESH
Land of opportunity

"Madhya Pradesh is the best example of a state's dedication, determination and good intent of governance, which can turn around and make the state an ideal place for investment."
Shri Narendra Modi
Prime Minister, India

"Madhya Pradesh, the heart of Incredible India, is one of the fastest growing economies in the country. With its business friendly policies and skilled labour force, we aspire to become the growth pillar of Make in India."
Shri Shivraj Singh Chouhan
Chief Minister, Madhya Pradesh

Amongst top five states in ease of doing business*

Centrally located logistic hub connected to 50% of India, will offer better benefits post GST

Single table system for fast-tracking of investments and business proposals

Stable government with transparent and investment friendly policies

Modern and supportive infrastructure

Excellent land bank, power surplus, ample water, productive and peaceful labour.

*As per World Bank and DIPP Ranking

GLOBAL INVESTORS SUMMIT | 22-23 OCTOBER, 2016 | Brilliant Convention Centre, Indore | For participation, register at www.investmp.com

PARTNER COUNTRIES
UK KOREA UAE JAPAN SINGAPORE

ORGANISED BY
TRIFAC

SiMPlified solutions... aMPlified opportunities

D79755

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

पहले वादे अब शब्दजाल में फंसाने की कोशिश

मुसलमानों के तीन तलाक को लेकर बहस शुरू हुई है. तुर्की की तरह कई मुस्लिम देश हैं, जहां तलाक़ और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित बहुत ही संयत कानून हैं. हमें यहां मुस्लिम लीडर्स को आपस में बहस शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि पति–पत्नी जब अलग हों, तो उसके लिए कोई अधिक सभ्य तरीका अख्तियार किया जाए. तीन तलाक़ और पत्नी को घर से निकाल देना शरिया के हिसाब से शायद जायज हो, लेकिन यह सभ्य तरीका नहीं है, जिसपर मुसलमानों समेत सभी सहमत हैं. लेकिन यह सामाजिक परिवर्तन है, जिसे विकसित होने देना चाहिए, न कि किसी अदालती फरमान द्वारा लागू करना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावकारी नहीं होगा. हालांकि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि संविधान पवित्र ग्रंथ है, सभी धर्म एक समान हैं, लेकिन उनके काम से यह ज़ाहिर नहीं होता है.

देश की राजनीति में उथल–पुथल है, क्योंकि अंधराष्ट्रीयता के शब्दजाल ने तथ्यात्मक बहस की जगह ले ली है. सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल और सरकार के दूसरे सुरक्षा तंत्र अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करते हैं. यह बात सच हो सकती है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने स्ट्राइक (सर्जिकल) करने के लिए सेना को क्लियरेंस दिया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इसका क्रेडिट लेना बचकाना है. जैसा पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि इस तरह के स्ट्राइक पहले भी हो चुके हैं और एलओसी के पास मौजूद सैनिक इसके बारे में जानते हैं. ठीक है कि गुणवत्ता के हिसाब से इस बार फर्क पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है. राहुल गांधी ने सही बात को गलत शब्दों में कहा. वो कहना ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सेना द्वारा बहाए गए खून से राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है. अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी ने हिंदी के सही शब्दों का चयन नहीं किया था. हास्यास्पद बात ये है कि मोहन भागवत ने राहुल गांधी के संदेह को ये कह कर सही साबित कर दिया कि यूपी चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा. तो फिर राहुल गांधी की आलोचना क्यों की जा रही है? बेशक उनके शब्दों के चयन को लेकर उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन उन्होंने जो कहा, उसकी आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा के चीफ के चीफ (मोहन भागवत) ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा. कुल मिला कर ये दुखद स्थिति है. ये अफवाह है कि राजनाथ सिंह इस उपलब्धि के आधार पर उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे. बांग्लादेश के निर्माण के बाद जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, तब बिल्कुल अलग वातावरण था. अभी कोई ऐसी महान घटना नहीं घटी है, न ही पाकिस्तान का विघटन हुआ है. जहां तक स्ट्राइक का सवाल है तो पाकिस्तान तो अक्सर स्ट्राइक कर रहा है, आपने एक बार किया. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. इसे लेकर आपको न तो क्षमाप्रार्थी होने की जरूरत है और न ही शोर मचाने की. इससे किसी का फायदा नहीं होगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं. औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है. उत्तर प्रदेश चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाने की बात चल रही है. इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पीछे रह गए हैं. ये बहुत दुख की बात है. पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमेशा पड़ोसी रहेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी. हमारी समस्याएं वहीं हैं, बेशक वो एक दिन में हल नहीं हो सकती हैं. प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में जो वादे किए थे, अब उन्हें लग रहा है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता है. विकास अपनी रफ्तार से होगा, लेकिन औद्योगिक विकास का पिछड़ना एक गंभीर विषय है. लेकिन यह अनुमानित था, क्योंकि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस केवल नारे थे. जो कोई भारत में कॉरपोरेट और बिजनेस की जानकारी रखता है, उसे पता है कि यहां कुछ भी नहीं बदला है. आयकर विभाग, कस्टम विभाग आदि की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहां भ्रष्टाचार के स्तर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहां की मुश्किलें पहले की तरह ही हैं.

अब कहा जा रहा है कि जीएसटी एक्ट अप्रैल से लागू होगा जो शायद एक गेम चेंजर साबित होगा. लेकिन दूसरे देशों में जहां जीएसटी लागू हुआ है, वहां का अनुभव बताता है कि जब यह लागू होता है तो महंगाई दर बढ़ जाती है. ये महंगाई दर तीन से पांच साल के बाद काबू में आती है. इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा.

मुसलमानों के तीन तलाक को लेकर बहस शुरू हुई है. तुर्की की तरह कई मुस्लिम देश हैं, जहां तलाक़ और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित बहुत ही संयत कानून हैं. हमें यहां मुस्लिम लीडर्स को आपस में बहस शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि पति–पत्नी जब अलग हों, तो उसके लिए कोई अधिक सभ्य तरीका अख्तियार किया जाए. तीन तलाक़ और पत्नी को घर से निकाल देना शरिया के हिसाब से शायद जायज हो, लेकिन यह सभ्य तरीका नहीं है, जिसपर मुसलमानों समेत सभी सहमत हैं. लेकिन यह सामाजिक परिवर्तन है, जिसे विकसित होने देना चाहिए, न कि किसी अदालती फरमान द्वारा लागू करना चाहिए, क्योंकि यह प्रभावकारी नहीं होगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं. औद्योगिक विकास पिछड़ रहा है. उत्तर प्रदेश चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाने की बात चल रही है. इसका मतलब है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पीछे रह गए हैं. ये बहुत दुख की बात है. पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमेशा पड़ोसी रहेगा.

हालांकि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि संविधान पवित्र ग्रंथ है, सभी धर्म एक समान हैं, लेकिन उनके काम से यह ज़ाहिर नहीं होता है. कश्मीर की मिसाल सामने है. भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जिसकी वजह से पीडीपी ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी. यह सबको मालूम है कि भाजपा आर्टिकल 370 समाप्त करना चाहती है. अगर कश्मीरियों के साथ आप ऐसा करेंगे तो बाक़ी मुसलमान क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि जब कश्मीरियों के साथ समझौता है और परिग्रहण का दस्तावेज़ है और फिर भी ये सब हो रहा है तब हमारी सुरक्षा का क्या होगा? बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उनमें असुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है. उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की जो देश के लिए ठीक नहीं है. मैं समझता हूं कि इस पर बेहतर सोच अपनाई जाए और बुद्धिमान लोग इसका दीर्घकालिक हल तलाश करें ताकि जनता के अलग–अलग वर्गों का गुस्सा खत्म हो. यह काम कौन करेगा, हमें मालूम नहीं है. प्रधानमंत्री अपने प्रशासन में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी पार्टी में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो दीर्घकालिक आधार पर इस मसले को निपटाने की कोशिश करे.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

राजस्थान का ये कैसा सुशासन

कवर स्टोरी–अमित शाह जी, राजस्थान की तरफ देखिए (10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016) पढ़ा. काफी अच्छी है. राजस्थान में कहा जाता है कि सुशासन है. लेकिन ये कैसा सुशासन है? शायद लेखक ने सही कहा है कि यह सुशासन, भारतीय जनता पार्टी मार्का सुशासन है. राजस्थान की प्रशासनिक हालत आज तिनी खराब है कि इसे ले कर कोई सवाल तक नहीं उठा रहा है. जाहिर है, जब कोई सवाल नहीं उठाएगा तो केंद्र में बैठे भाजपा के बड़े नेता इस पर ध्यान क्यों देंगे? प्रशासनिक तौर पर राजस्थान की हालत खराब हो चुकी है.

–प्रभाकर कुमार, *जयपुर, राजस्थान.*

कश्मीर में शांति कब बहाल होगी

कश्मीर अविश्वास के बीच स्थिति सामान्य हो रही है... (10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में हारून रेशी ने बताया कि कश्मीर में मोहल्ले की मस्जिदों में नारेबाजियों का सिलसिला और पथराव की घटनाओं में काफी कमी आई है. लेकिन क्या कश्मीर के लोग सचमुच शांत हो गए है? क्या उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया है? ऐसा लगता नहीं है. पिछले तीन महीनों के दौरान कश्मीर में जो कुछ हुआ है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं है. तीन महीने कश्मीर बंद रहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों की हालत खराब हो गई है. ऐसे में सरकार को कोई समाधान निकालना चाहिए.

–सरफराज आलम, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

सरकारी लूट का नमूना

सैंया भए कोतवाल तब डर काहे का– स्वास्थ्य मंत्री ने

अपनी संस्था के बारे में भेजी फर्जी रिपोर्ट (10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016) शीर्षक लेख में प्रशान्त शरण ने सही लिखा है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का यह बयान अक्षरश: सही प्रतीत हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड के राजनेताओं ने केवल लूटने का काम किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी इसी काम में लगे हुए है. स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर मारामारी मची हुई है. **–गौतम कुमार,** *रांची, झारखंड.*

दलितों के साथ भेदभाव

आलेख– दलित उत्पीड़न में भाजपा शासित राज्य आगे (10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016) पढ़ा. राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा हाल में जारी की गई क्राइम इन इंडिया– 2015 रिपोर्ट से एक बात फिर उभर कर सामने आई है कि भाजपा शासित राज्य दलित उत्पीड़न के मामले में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हैं. गुजरात की घटना ताजा उदाहरण है कि कैसे भाजपा शासित राज्यों में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है. सवाल है कि फिर भाजपा कैसे दलित हित की बात करती है.

– मुकेश कुमार, *उन्नाव, उत्तर प्रदेश*

गिलानी का बयान निंदनीय है

संतोष भारतीय की संपादकीय जब तोप मुकाबिल हो, गिलानी साहब, आपका ये बयान दुखद है (10 अक्टूबर– 16 अक्टूबर 2016) पढ़ा. इसने बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिलकुल सही कहा है कि क्या कश्मीर के कुछ नेता पाकिस्तान के सवाल को, सीमा के सवाल को और कश्मीर के सवाल को एक मानते हैं या कश्मीर और कश्मीर के लोगों का सवाल अलग है ओर पाकिस्तान का सवाल अलग है, ये मानते हैं. अगर इस बात को गिलानी साहब भी समझते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते. इस तरह का बयान दे कर वे अपने आंदोलन को और कमजोर कर रहे है.

–सोमा बनर्जी, *कोलकाता, पश्चिम बंगाल.*

सर्जिकल स्ट्राइक कितना कारगर

एक देशभक्त नागरिक होने के नाते मैं सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल तो नहीं उठा सकता लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से हमने हासिल क्या किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाजपा अब इस सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने की जो कोशिश कर रही है, क्या इससे सेना का राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है. यह दुखद है. यह भी सच है कि एलओसी पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को बार–बार मजा चखाया है लेकिन कभी इस पर शोर नहीं मचाया गया? इस बार आखिर क्यों सरकार इतना शोर मचा रही है?

– नीरज कुमार, *देवरिया*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स– आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख–कान–नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव–विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)–201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, आपको कश्मीरियों से मिलना चाहिए

हमारा देश महान देश है. इस देश में बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं. पूजा-पाठ करते हैं. पत्थरों में भगवान का दर्शन करते हैं. पेड़ों को पानी देते हैं. पौधों की पूजा करते हैं. चांद-सूरज को अर्घ्य देते हैं. उनसे अपने सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, लेकिन इंसानों को भूल जाते हैं. इस देश के 124 करोड़ लोगों को याद नहीं आता कि हमारे ही भाई पिछले 99 दिनों से बिना काम-काज, बिना दवाई, बिना इलाज, बेरोजगार बैठे हैं. हमारे ही देश के एक बड़े हिस्से में पिछले 99 दिनों से स्कूल-कॉलेज बंद हैं. पढ़ाई ठप है. लेकिन 124 करोड़ लोग, जिनकी धर्म में महान आस्था है और जो चींटी को भी मारना गुनाह समझते हैं, वे मुंह सिले हुए, आंखें बंद किए हुए इस स्थिति को अनदेखा कर रहे हैं. ये कम से कम एक बात की तरफ इशारा करता है कि हम 124 करोड़ लोगों ने, मैं कश्मीर की 60 लाख जनसंख्या को अलग कर रहा हूं, इसलिए 124 करोड़ लोग कहता हूं, कभी भी कश्मीर के लोगों को भारत का अविभाज्य हिस्सा समझा ही नहीं. हमने कभी उनका वो दर्द महसूस नहीं किया, जो उन्हें व्यवस्था से मिलता रहा है. हमने उनके आंसुओं को अपने आंसुओं से अलग रखा. हमने उनके और अपने दर्द को एक जैसा माना ही नहीं. ऐसा लगा जैसे हमारा खून लाल है और उनका खून किसी और रंग का है. वहीं पर पूजा-पाठ, धर्म, प्यार-मोहब्बत, आस्था, मानवता, इन सब पर शंका पैदा हो जाती है.

कश्मीर में 99 दिन पूरे हो गए. वहां पर दुकानें बंद हैं. सड़कों पर सार्वजनिक वाहन ठप हैं. इतना ही नहीं, वो वर्ग जो रोजाना कमा कर खाता है, उसकी दैनिक आमदनी बंद है और वो लोग भी जो व्यापार करते हैं या गैर सरकारी काम में जुटे हुए हैं, उनकी भी आमदनी बंद है. घरों में राशन खत्म हो रहा है. अभी-अभी खबर आई है कि जहां सरकार 5 किलो चावल देती थी, अब 4 किलो प्रति व्यक्ति चावल देगी. केरोसिन की और राशनिंग कर दी गई है. ये स्थिति न भारत सरकार को चिंतित करती है और न ही भारत के 124 करोड़ लोगों को, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे पूरा हिन्दुस्तान अपने एक अंग को भूल गया है या शायद कुछ ऐसा हुआ है कि उस अंग का दर्द महसूस ही नहीं होता है. ये स्थिति पिछले 65 वर्षों से है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये स्थिति पिछले कुछ वर्षों से जरूर है. ये 99 दिन इस स्थिति को देखने के लिए काफी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि भारत के 124 करोड़ लोगों की आंखें बंद हैं.

कश्मीर के लोग क्या करें? उन्हें लगता है कि हिन्दुस्तान के बाकी प्रांतों के लोग उन्हें परित्यक्त व्यक्ति मानते हैं. हिन्दुस्तान के लोग उनके दर्द से अपना रिश्ता महसूस नहीं करते और उन्हें लगता है कि उनके भविष्य की चिंता जिस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार को नहीं है, उसी तरह से हिन्दुस्तान के लोगों को भी नहीं है. सवाल उठता है कि क्या ये स्थिति हम न्यायोचित मानते हैं? हम हर चीज में न्याय तलाशते हैं, चाहे वो सरकार से हो, न्यायालय से या फिर ईश्वर से, लेकिन हम कश्मीर के लिए, वहां के लोगों के लिए न्याय नहीं तलाशते. हमें इतिहास भी नहीं पता है और हम इतिहास जानना भी नहीं चाहते कि किन परिस्थितियों में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का समझौता हुआ था. क्यों जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तब कश्मीर में क्विट डोगरा मूवमेंट हुआ? किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ शामिल होने का फैसला लिया? और, आखिर आर्टिकल 370 क्या है? हमारे मित्र, जो टेलीविजन के न्यूज रूम में बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ या मानवता की बात करने वाले लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं. ये ऐसे लोग हैं जो देश को ऐसे समाज में बदलना चाहते हैं, जिस समाज ने गैलिलियो की उस अवधारणा को नकार दिया था कि पृथ्वी गोल है और उसी समाज ने पृथ्वी को गोल कहने के लिए गैलिलियो को फांसी की सजा दे दी थी. आज 21वीं शताब्दी में टेलीविजन के न्यूजरूम में बैठे मित्र पूरे देश को उसी तरह के समाज में बदल देना चाहते हैं. हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारी खबरों के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता और लोग उसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं, इस स्थिति को लाने में भी हमारे बहुत सारे साथियों का अहम योगदान है.

अभी सवाल कश्मीर का है. सरकार से हम पुन: अनुरोध करते हैं कि हम लाओस, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, अफ्रीकी देश सूडान, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान हर जगह अपने पैर फंसा रहे हैं. वहां शांति रहे, इसलिए अपनी सेना भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं. उनके विकास के लिए मदद भेज रहे हैं, लेकिन हम अपने ही देश के एक बड़े हिस्से के लोगों को, जिन्हें हम कश्मीर के लोग कहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं.

अभी सवाल कश्मीर का है. सरकार से हम पुन: अनुरोध करते हैं कि हम लाओस, कंबोडिया, चीन, अमेरिका, अफ्रीकी देश सूडान, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान हर जगह अपने पैर फंसा रहे हैं. वहां शांति रहे, इसलिए अपनी सेना भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं. उनके विकास के लिए मदद भेज रहे हैं, लेकिन हम अपने ही देश के एक बड़े हिस्से के लोगों को, जिन्हें हम कश्मीर के लोग कहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. न प्रधानमंत्री जी के पास वक्त है, न गृहमंत्री जी के पास वक्त है. गृहमंत्री जी कश्मीर गए, उनका बहुत स्वागत हुआ, लेकिन वहां जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का एक इतिहास रहा है. इस प्रतिनिधिमंडल से कश्मीर के लोग विरोधस्वरूप नहीं मिले क्योंकि उनका कहना था कि ये प्रतिनिधिमंडल आता है, बात करता है और उनकी बातों और वादों पर अमल नहीं होता. यहां तक कि उनकी रिपोर्ट का भी कश्मीर के लोगों को पता नहीं चलता. इस स्थिति में क्या प्रधानमंत्री जी, आपसे ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि अपने ही देश का एक हिस्सा अनाथ सा हो गया है, लकवाग्रस्त हो गया है, निराशा के चरम बिंदु पर पहुंच गया है और उसका भारतीय संसद, भारतीय जनता और भारतीय संविधान में कोई भरोसा नहीं रह गया है. क्या अपने ही देश के लोगों में विश्वास जगाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं पर भी कोई निराशा हो, कहीं पर कोई अत्याचार हो, लोग किससे कहेंगे? लोग आप ही से कहेंगे. मैं हिंदुस्तान के उन लोगों की तरफ से, जिनका मानवता में, भारतीयता में, बंधुत्व में विश्वास है, आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप तत्काल कश्मीर जाएं, दो दिन वहां रहें, लोगों से मिलें और उसके बाद आप जो फैसला करेंगे, विश्वास मानिए, कश्मीर उस फैसले को मानेगा. आखिर, यही कश्मीरी लोग हैं, जो आज भी अटलबिहारी वाजपेयी जी को भगवान की तरह याद करते हैं. अटलबिहारी वाजपेयी जी में क्या था, जो आप में नहीं है? मुझे लगता है कि आज आप अटलबिहारी वाजपेयी से ज्यादा शक्तिशाली हैं, अटलबिहारी वाजपेयी से ज्यादा अच्छा फैसला कर पाने की स्थिति में हैं. अगर एक बार आप कश्मीर चले जाएं, तो ये गतिरोध, ये दर्द का तूफान अवश्य रुकेगा. आपके राजनीतिक विरोधी कह सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी से कोई अनुरोध नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सच्चाई है. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप तत्काल कश्मीर जाएं और कश्मीर की स्थिति को और भयावह होने से बचा लें ताकि कश्मीर के लोग निराशा की चरम सीमा को लांघ कर पूरी तरह हमसे अलग न हो जाएं. फिर हमें एक बड़े हत्याकांड, जिसे नरसंहार कहा जाता है, की खबर सुनने के लिए अपने को तैयार कर लेना चाहिए. और वो हत्या लोगों की होगी, लोगों के आशाओं की होगी, लोगों के सपनों की होगी. ■

editor@chauthiduniya.com

मैं हिंदुस्तान के उन लोगों की तरफ से, जिनका मानवता में, भारतीयता में, बंधुत्व में विश्वास है, आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप तत्काल कश्मीर जाएं, दो दिन वहां रहें, लोगों से मिलें और उसके बाद आप जो फैसला करेंगे, विश्वास मानिए, कश्मीर उस फैसले को मानेगा. आखिर, यही कश्मीरी लोग हैं, जो आज भी अटलबिहारी वाजपेयी जी को भगवान की तरह याद करते हैं. अटलबिहारी वाजपेयी जी में क्या था, जो आप में नहीं है?

मत-मतांतर

लोकभाषा में हो लोक-राज

डॉ. राम मनोहर लोहिया

मातृभाषा यानी उड़िया, बांग्ला, तमिल और तेलुगु और वैसे ही हिन्दी. चीन के मुकाबले में हिन्दुस्तान की दयनीय अवस्था और लज्जास्पद स्थिति कई कारणों से है, जिनमें से भाषा कोई कम मुख्य कारण नहीं है. उद्योग, ज्ञान-विज्ञान, हुनर आदि में हिन्दुस्तान से चीन कहीं ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उसने मातृभाषा को शासन का माध्यम बनाया. हमारे अपने देश में अल्पमत द्वारा शासन और शोषण की भाषा अंग्रेजी के इस्तेमाल से ज्ञान-विज्ञान और उद्योगीकरण सिकुड़ गया है. भाषा के संबंध में हिन्दुस्तान के संविधान में कुछ असामान्य व्यवस्था है. यह कहना गलत है कि वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों की अनुमति देता है. उसमें जो व्यवस्था है वह यह कि 1950 और 1965 के बीच अंग्रेजी की हैसियत कम होती जाए और हिन्दी की बढ़ती जाए और लक्ष्य यह है कि उस अवधि के बाद अंग्रेजी न रहे. राष्ट्रपति बनने के पहले डॉ. राधाकृष्णन दस साल तक उपराष्ट्रपति थे. दस साल से वे संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेते रहे और शपथ के ही कारण जनता ने उन्हें वहां विराजमान रखा. उन्होंने इस कसम को निभाया, क्या वे हिन्दी नहीं सीख सकते थे? दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि केवल सोशलिस्ट पार्टी ही ऐसा तत्व है जो संविधान के प्रति वफादार है, लेकिन वह महसूस करती है कि गैर हिन्दी राज्यों में हिन्दी से चिढ़ काफी ज्यादा हो गयी है. यह मानना हद दर्जे का पागलपन होगा कि वहां के शासक और मध्यम वर्ग वाले कभी हिन्दी को स्वीकार करेंगे.

इसलिए समाजवादी दल मातृभाषा के दृष्टिकोण से इस समस्या का हल निकाल रहा है. जो कोई मातृभाषा हो, वह स्थापित की जाए और हिन्दी केवल ऐच्छिक रहे. तट-सूबे तीन में से किसी एक बात को अपनी पसंद से स्वीकार कर सकते हैं बहुभाषी केंद्र, संरक्षण के साथ हिन्दी केंद्र और विभाजित केंद्र. इस तरह गैर हिन्दी इलाकों को संविधान में जो व्यवस्था है, उससे ज्यादा सहूलियत समाजवादी दल दे रहा है. हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति अपनी मातृभाषा में बोलें और हम चाहते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी के कट्टरवादी अपनी बकवास बन्द करें और हमारे बारे में निरन्तर झूठी बातें न करें. जब तक हिन्दुस्तान की जनता अपनी भाषा की समस्या के बारे में जागरूक नहीं होती देश डूब जाएगा. आज देश में तीन का ही आदर है: 1. सरकार सम्मानित नेता और मंत्री 2. बड़े सरकारी अफसर और 3. करोड़पति. बाकी जनता का तो कचहरियों, सरकारी दफ़्तरों आदि स्थानों में हर जगह निरादर होता है. यहां पर मैं अपने ऊपर बीती कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूं. 19 जनवरी को सुबह सारनाथ के हिरन देखने को निकला. वहां लड़कों का बगीचा भी था. एक लोहे की बनी हुई ढालू चादर पर देहात के पांच-छह बच्चे फिसल रहे थे. किलकारी मार कर प्रसन्नता के साथ बच्चे खेल रहे थे. इतने में एक सरकारी अफसर अपने

चपरासी के साथ उस बगीचे में आया और बच्चों को डांट कर हटाने लगा. मुझसे नहीं रहा गया. मैंने पूछा, बच्चों को क्यों भगा रहे हो? अफसर ने जवाब दिया, गांव के बच्चे हैं. मैंने कहा, क्या गांव के बच्चे, बच्चे नहीं हैं? तब मुझे कुछ गुस्सा आया और मैंने उस अफसर से कहा, फिर आगे कभी ऐसा मत करना. चपरासी ने भी बोलने की कोशिश की. मुझे उन दोनों से जोर देकर बोलना पड़ा कि आगे कभी ऐसा न करना. मुझे खुशी हुई कि वे देहाती फटे-मैले कपड़ों के बच्चे फिर वहां आकर खेलने लगे. उस दिन मुझे खुशी हुई कि मेरे जैसा मामूली आदमी भी हिन्दुस्तान के पांच-छह बच्चे नागरिकों को उनकी मिलकियत दिला सका. जुल्म को सह लेना ज्यादा खराब है, बनिस्बत गुस्सा करने के. ऐसा लगता है कि हिन्दुतान के असली नागरिक बाहर हटा दिए गए हैं और कमरे के भीतर बेईमान, विदेशी, जंगली और असभ्य हैं. गौतमबुद्ध ने जरूर अच्छा कहा था: अक्रोधेन क्रोधं, लेकिन अन्याय के मुकाबले में? मेरे साथ दूसरी घटना आबू पर्वत की है. मैं अकेला था. मुझे तार भेजना था. तार-घर गया. खैर, मैं तो वैसे ही हिन्दी का प्रयोग करता हूं. तार-फॉर्म पर भी लिखा था, तार हिन्दी में भेजिए, हिन्दी में तार लिखकर दिया. तार बाबू ने कहा, अंग्रेजी में लिखो. मैंने कहा, क्यों लिखें? फिर तार बाबू ने कहा, कहां से इतने हिन्दी के तार लाएं? मैंने कहा, तब ऐसा फार्म क्यों देते हो, जिस पर लिखा है, तार हिन्दी में भेजिए. तब तार बाबू ने संभलकर कहा, हमारे ऊपर के अफसर ने ऐसा फार्म भेजवा दिया है. असल में इस गलती के लिए तार बाबू को माफी मांगनी चाहिए थी. अपने ऊपर के अफसर की गलती के लिए साधारण जनता का निरादर क्यों किया जाय? जनता के लिए तो सरकार वही है, जो उसके संपर्क में आए, चाहे वह छोटे से छोटे नौकर क्यों न हों. मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि घमंड करें. इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें, जिनके मां-बाप अगर शरीर से नहीं, आत्मा से अंग्रेज रहे हों.

एक प्रश्न अवश्य उठता है. जब कोई पुराना देश अपने को आधुनिक बनाए, तब संभव है कि उसे भूषा-भाषा के मामले में भी परिवर्तन करना पड़े. भाषा के परिवर्तन का तो एक अर्थ होता है कि वह अपनी लोकभाषा व लोकभाषाओं को समृद्ध बनाए. उनमें सब तरह के ज्ञान का समावेश करे. भूषा का परिवर्तन दूसरे ढंग का हो हो सकता है, लेकिन वह ढंग हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख मूंद कर या तो आधुनिक कहलाने वाले देशों की भूषा की नकल की जाए, या किसी पुराने सामंती जमाने की पोशाक अपनायी जाए. हिन्दुस्तान की आबो-हवा को देखते हुए और आधुनिकता के समय, सादगी और समता की कीमत को पहचानते हुए गला-लंगोट (टाई) और खुले कॉलर की कोट उसी तरह बंदरी पोशाक है, जिस तरह चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी. आधुनिकता के नाम पर ऐसी पोशाकों को अपनाना या तो मूर्खता है, या सामंती शासकों का हथकंडा. मैं यह समझ सकता हूं कि लोग पतलून अथवा जोधपुर अथवा बुशकोट अपनाएं, और धोती, कुरता-पैजामा के साथ-साथ उन्हें हिन्दुस्तान की पोशाकों में शामिल करें. हमें उतना ही विरोध दकियानूसी और सांप्रदायिक चोटी-दाढ़ी और जनेऊ का करना चाहिए, जितना सामंती चूड़ीदार पैजामा और गला-लंगोट का. ■

feedback@chauthiduniya.com

हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति अपनी मातृभाषा में बोलें और हम चाहते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी के कट्टरवादी अपनी बकवास बन्द करें और हमारे बारे में निरन्तर झूठी बातें न करें. जब तक हिन्दुस्तान की जनता अपनी भाषा की समस्या के बारे में जागरूक नहीं होती देश डूब जाएगा. आज देश में तीन का ही आदर है: 1. सरकार सम्मानित नेता और मंत्री 2. बड़े सरकारी अफसर और 3. करोड़पति. बाकी जनता का तो कचहरियों, सरकारी दफ़्तरों आदि स्थानों में हर जगह निरादर होता है.

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

महागठबंधन की कमज़ोर कड़ी बने राजबल्लभ

राजद और जद यू के बीच का यह मनमुटाव दरअसल एक दूसरे दल को अपनी सीमा याद दिलते रहने की रणनीति का हिस्सा है. राजद सरकार में सबसे बड़ा दल है, जबकि नीतीश कुमार एक छोटे दल के नेता होने के बावजूद, चुनाव पूर्व शर्तों के तहत मुख्यमंत्री बने हैं. इस प्रकार समय-समय पर राजद उन्हें जहां यह आभास कराता रहता है कि वह गठबंधन सरकार का बड़ा घटक दल है, वहीं नीतीश राजद को यह अभास दिलाने से नहीं चूकते कि वह मुख्यमंत्री हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

इ से एक संयोग माना जा सकता है, जिस दिन राजद के विवादित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा दी गयी जमानत रद्द कर दी. उसी दिन राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया. यह 30 सितंबर की बात है. राजबल्लभ पर बीते फरवरी में एक नाबालिग से रेप का मामला दर्ज हुआ था और वह जेल में थे. इसी घटना के बाद राजद ने उन्हें दल से निलंबित कर दिया था. 30 सितंबर को राजबल्लभ की जमानत बड़ी ख़बर नहीं बन पाई थी, क्योंकि उस दिन शहाबुद्दीन का मामला सुर्खियां बटोर रहा था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राजद का पिछले एक महीने से जारी सरदर्द ख़त्म हो गया था. भले ही सर्वोच्च अदालत द्वारा शहाबुद्दीन को तत्काल जेल में डालने के हुक्म के बाद वह मामला जरा ठंडा पड़ता दिखा, पर उसी दिन राजबल्लभ प्रकरण राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ चुका था. कमोबेश राजबल्लभ प्रकरण राजद के लिए उतनी ही जटिल समस्या के रूप में

> राजबल्लभ पर नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोप फरवरी के पहले सप्ताह में लगाया था. उसके बाद जब पुलिस ने उन पर एफआईआर किया, तो वह हफ्तों भागते रहे. इस बीच उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे. उनका पुलिस की पकड़ से दूर रहना विपक्षी भाजपा के लिए लगातार हमला का कारण बनता रहा. इस बीच राजद अपनी छवि बचाने के लिए अपने विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित करने की घोषणा कर के अपना बोझ कम करने की कोशिश की.

सामने आया था. हालांकि इसकी तीव्रता शहाबुद्दीन प्रकरण से काफी कम थी. शहाबुद्दीन का विवाद राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाला था, जबकि राजबल्लभ विवाद उतना हाईप्रोफाइल नहीं था. वरना इस मामले में राजद को विपक्ष के आक्रमण और मीडिया के सवालों का सामना तो था ही, साथ ही सत्ता के सहयोगी दल वाली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का व्यवहार भी ठीक वैसा ही था जैसा शहाबुद्दीन मामले था. पटना हाईकोर्ट द्वारा शहाबुद्दीन को मिली जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चुनौती दी थी, उसी तरह राजबल्लभ मामले में भी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ताकि वह उनकी जमानत रद्द करवा सके. धार्मिक कर्मकांड में मजबूत आस्था रखने वाले लालू प्रसाद को राजबल्लभ प्रकरण, किसी चलचित्र के फ्लैशबैक की तरह लग रहा होगा, क्योंकि पिछले एक महीने में शहाबुद्दीन प्रकरण में राष्ट्रीय जनता दल जिन तकनीकी व राजनीतिक सरदर्द से जूझ रहा था, उन्हीं चुनौतियों का सामना उसे राजबल्लभ मामले में फेस करना पड़ा. बल्कि यूं कहें कि राजबल्लभ प्रकरण में लालू को अपने बचाव के लिए कुछ ज्यादा ही मशक्कत तब करनी पड़ी, जब दशहरा के चंद दिन पहले राजबल्लभ,

राजबल्लभ होने का मतलब

नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव रेप जैसे गंभीर आरोपों में घिरे हैं. जेल और बेल के चक्कर में बुरी तरह फंसे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके परिवार पर ऐसा आरोप पहली बार लगा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 1998 में राजबल्लभ के भाई विनोद यादव धनबाद की एक लड़की से बलात्कार के आरोप में घिरे थे. यह घटना गेलैक्सी होटल में घटी थी, तब काफी कोहराम मचा था. लेकिन कुछ हफ्तों की चुप्पी के बाद राजबल्लभ ने रेप पीड़िता का एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें लड़की अपने आरोप से मुकर गई थी. उस समय राजबल्लभ 1995 के विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुके थे. बाद में वह तत्कालीन राबड़ी देवी मंत्रीमंडल में मंत्री भी बने थे. नवादा जिला, जहां से वह असेम्बली में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, पिछले कई दशकों से हिंसा की चपेट में रहा है. कई नरसंहार भी यहां हुए हैं. क्षेत्र में भूमिहारों और यादवों के वर्चस्व की लड़ाई सन दो हज़ार तक काफी सुर्खियों में रही है.

राजबल्लभ के राजनीतिक और व्यापारिक रसूख को नवादा में चुनौती देना कई नेताओं के लिए कठिन रहा है. नवादा और उसके इर्द-गिर्द की पहाड़ियों पर उनकी मिलकियत को चुनौति देने की कोशिश वह अक्सर नाकाम करते रहे हैं. कुछ साल पहले जब पहाड़ों के खनन के लिए नीलामी हुई, तो उन्हें सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली भी नीलामी में पछाड़ने में नाकाम रहे थे. ऐसा नहीं है कि एक मज़बूत व्यापारी होने के कारण ही राजबल्लभ राजद के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. राजबल्लभ का परिवार नवादा का सबसे सशक्त राजनीतिक परिवार के रूप में जाना जाता है. राजबल्लभ के पिता जेहल यादव का राजनीतिक व सामाजिक रसूख काफी पहले से ही मज़बूत था, जिसका लाभ राजबल्लभ को मिला. राजबल्लभ के बड़े भाई नवादा की राजनीति में पहले से सरगर्म रहे और विधायक बने थे. लेकिन उनके निधन के बाद राजबल्लभ ने वहां अपना सिक्का जमाया. राजद को इस बात का एहसास रहा है कि नवादा की राजनीति में राजबल्लभ के बिना उसका दबदबा बनाये रखना आसान नहीं होगा.■

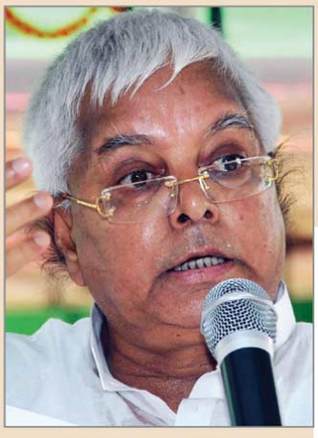

अचानक लालू-राबड़ी के सरकारी आवास से बाहर आते दिखे. जैसे ही यह तस्वीर मीडिया की सुर्खी बनी और बलात्कार के आरोपी राजबल्लभ की लालू से मुलाकात पर सवाल उठाये जाने लगे, तो मजबूरन लालू प्रसाद को मीडिया के सामने आ कर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके घर आता है, तो क्या मैं उसे भगा दूंगा. भले ही लालू प्रसाद ने राजबल्लभ से अपनी मुलाकात के बारे में सफाई देकर अपना पक्ष रख दिया हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को उनकी यह बात पच नहीं रही. लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद एक अण्णे मार्ग की जिस कोठी में रहते हैं, वहां एक परिंदा भी तब ही पर मार सकता है, जब उनकी इज़ाजत हो. बताया जाता है कि लालू प्रसाद से राजबल्लभ की मुलाकात दो घंटे तक चली. इस दौरान उनसे उनकी क्या बात हुई यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन राजबल्लभ ने मीडिया से इतना कहा कि वह लालू जी को दशहरा की बधाई देने गये थे.

राजबल्लभ पर नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोप फरवरी के पहले सप्ताह में लगाया था. उसके बाद जब पुलिस ने उन पर एफआईआर किया, तो वह हफ्तों भागते रहे. इस बीच उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे. उनका पुलिस की पकड़ से दूर रहना विपक्षी भाजपा के लिए लगातार हमला का कारण बनता रहा. इस बीच राजद अपनी छवि बचाने के लिए अपने विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित करने की घोषणा कर के अपना बोझ कम करने की कोशिश की. उधर राजबल्लभ को अदालत में सरेंडर करना पड़ा और जेल जाना पड़ा. लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही लालू प्रसाद से उनके घर जा कर मिलने की घटना को विपक्षी दल ने इस रूप में लिया कि राजद ने उन्हें भले ही निलंबित कर दिया हो, पर लालू प्रसाद को राजबल्लभ मोह पहली की तरह बरकरार है. इस मामले में राजबल्लभ यादव के लिए चिंता का कारण सिर्फ विपक्षी भाजपा के हमलावर रुख के कारण ही नहीं है. उनकी परेशानी का इससे बड़ा कारण खुद नीतीश सरकार का वह कदम है, जिसकेतहत उसने राजबल्लभ की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई करते हुए राजबल्लभ को नोटिस दे कर 17 अक्टूबर तक उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है. लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि शहाबुद्दीन और राजबल्लभ प्रकरण के बाद महा-गठबंधन सरकार के दो महत्वपूर्ण धड़ों राजद और जद यू के बीच का मनमुटाव एक गहरा हुआ है. आमतौर पर किसी मामले में हाईकोर्ट अगर किसी अभियुक्त को जमानत देता है, तो सरकार उस मामले में नहीं पड़ती. लेकिन राजद से जुड़े दो नेताओं-शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव के मामले में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उससे यह ज़रूर ज़ाहिर होता है कि दोनों दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है. दरअसल अनेक मुद्दों पर गठबंधन सरकार के बीच आपसी असहमति समय-समय पर देखने को मिलती रही है. शराबबंदी के मामले पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना रुख कड़ा कर रखा है, उससे पहले से ही राजद चिंतित है. इसी क्रम में शहाबुद्दीन और राजबल्लभ मामले में नीतीश कुमार के रवैये ने राजद के लिए और ही परेशानियां बढ़ाई हैं.

राजद और जद यू के बीच का यह मनमुटाव दरअसल एक दूसरे दल को अपनी सीमा याद दिलते रहने की रणनीति का हिस्सा है. राजद सरकार में सबसे बड़ा दल है, जबकि नीतीश कुमार एक छोटे दल के नेता होने के बावजूद, चुनाव पूर्व शर्तों के तहत मुख्यमंत्री बने हैं. इस प्रकार समय-समय पर राजद उन्हें जहां यह आभास कराता रहता है कि वह गठबंधन सरकार का बड़ा घटक दल है, वहीं नीतीश राजद को यह अभास दिलाने से नहीं चूकते कि वह मुख्यमंत्री हैं. हालांकि दोनों दलों को पता है कि उनके बीच की कड़वाहट उनके संबंधों की बलि लेने की हद तक नहीं जा सकता,क्योंकि दोनों दलों को इस हक़ीक़त का बखूबी पता है कि गैर भाजपा और गैर संघवाद को मज़बूती देने के लिए दोनों का साथ बना रहना ज़रूरी है.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

शिवहर : करोड़ों खर्च के बाद भी लाइफ लाइन का हाल बेहाल

2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चले सत्ता परिवर्तन की लहर में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगर बिहार में शासन का कमान मिला, तो सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 के कटौझा की पीढ़ा से जनता को मुक्ति दिलाना पहली प्राथमिकता होगी. चुनाव बाद मिले जनादेश से जब नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तब उन्होंने कटौझा स्थित बागमती नदी पर रामवृक्ष बेनीपुरी सेतू का निर्माण कराने का कार्य किया. सड़कों की बदहाली से लोगों को मुक्ति मिली. कटौझा में साल के तीन माह तक भारी परेशानी का सामना करने वाले लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा. सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर रहा. परंतु निर्माण एजेंसी के कार्य के धीमा रफ़्तार का आलम रहा कि अब तक सड़क का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है और न ही निर्मित सड़क की सही तरीके से देखभाल. एनएच-77 के धर्मपुर चौक के समीप सड़क के पूर्वी भाग में बरसात के कारण ऐसा होल बना है, जो बाहर से नज़र नहीं आ रहा है.

वाल्मीकि कुमार

तकरीबन दो दशक पूर्व 1994 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजधानी पटना समेत देश के अन्य स्थानों से मां सीता की पावन जन्म स्थली सीतामढ़ी को बेहतर सड़क मार्ग से जोड़ने को लेकर पहली बार पहल की गयी थी. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भुवनचंद खंडूरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभव पहल की थी. इस कार्य के लिए सीतामढ़ी के तत्कालीन सांसद रहे नवल किशोर राय ने अहम योगदान दिया था. बाद के सालों में सत्ता परिवर्तन होता गया और सांसद रहे सीताराम यादव व डॉ. अर्जुन राय ने भी अपने स्तर से विकास को लेकर प्रयासरत रहे. इसी कड़ी में इस सड़क को फोरलेन में परिवर्तित कराने को लेकर केंद्रीय मंत्री रहे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी प्रयास किया था. उन्होंने केंद्रीय मंत्री टीआर बालू को लाकर सड़क का मुआयना भी कराया था.

बताया जाता है कि सरकारी सहमति के बाद फोरलेन के लिए जमीन का अधिग्रहण की कार्रवाई भी हुई, लेकिन सड़क का निर्माण फोरलेन के रूप में नहीं कराया जा सका. फोरलेन के रूप में हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक हीं कार्य कराया गया. कार्य एजेंसी सी एंड सी कंपनी के कार्य रफ्तार का आलम है कि अब तक कार्य अधर में लटका है. जानकारों का कहना है कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी मार्ग में एनएच-77 को कई स्थानों पर निर्माण कंपनी ने जर्जर हाल में छोड़ दिया है. नतीजा है कि लोगों को भारी तवाही झेलने की विवशता बनी है. सड़क के अलावा पुलों को भी हादसा के इंतजार में छोड़ दिया गया है.

इसका एक उदाहरण सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर मार्ग में गोपालपुर में मौजूद है. जहां पुल निर्माण को लेकर कई पाया का निर्माण कार्य को अधर में छोड़ दिया गया है. नतीजा है कि अब तक पुराने जर्जर हो चुके पुल से हीं वाहनों का परिचालन जारी है. दशकों पूर्व निर्मित पुल अब इस हाल में पहुंच चुकी है कि कभी भी यह भयावह हादसा के लिए चर्चा का केंद्र बन सकता है. मगर ताज्जुब की बात यह कि गोपालपुर से लेकर बेदौल गांव तक का जर्जर सड़क सीतामढ़ी जिले के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दे रहा. मानो सभी को इस पथ में किसी दुर्घटना का इंतजार हो. जनता का हमदर्द होने का दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधियों के सजगता का आलम है कि कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद टॉल टैक्स की वसूली की जा रही है. लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है. निर्माण एजेंसी के मनमानी का आलम है कि नये सड़क को जहां अधर में लटका रखा है. वहीं पुराने एनएच का मरम्मत तक कराने को तैयार नहीं है. जब प्रशासनिक शिकंजा कसता है, तब थोड़ा बहुत लिपापोती कर गुम हो जाती है. निर्माण कार्य में लापरवाही समेत अन्य मसलों को लेकर हाल हीं में पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने एक शिटमंडल के साथ जिला पदाधिकारी राजीव रौशन से मुलाकात कर मांग पत्र भी सौंपा है.

अब एक नज़र दोनों हीं महत्वपूर्ण पथों पर डालना आवश्यक है. बताते चलें कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चले सत्ता परिवर्तन की लहर में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगर बिहार में शासन का कमान मिला, तो सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 के कटौझा की पीढ़ा से जनता को मुक्ति दिलाना पहली प्राथमिकता होगी. चुनाव बाद मिले जनादेश से जब नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तब उन्होंने कटौझा स्थित बागमती नदी पर रामवृक्ष बेनीपुरी सेतू का निर्माण कराने का कार्य किया. सड़कों की बदहाली से लोगों को मुक्ति मिली. कटौझा में साल के तीन माह तक भारी परेशानी का सामना करने वाले लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा. सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर रहा. परंतु निर्माण एजेंसी के कार्य के धीमा रफ़्तार का आलम रहा कि अब तक सड़क का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है और न ही निर्मित सड़क की सही तरीके से देखभाल. एनएच-77 के धर्मपुर चौक के समीप सड़क के पूर्वी भाग में बरसात के कारण ऐसा होल बना है, जो बाहर से नज़र नहीं आ रहा है. जबकि अंदर ही अंदर सड़क के काफी भाग में मिट्टी धंस चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी कोई इसे देखने को तैयार नहीं है. अगर समय रहते समुचित मरम्मत नहीं कराया गया, तो कभी भी भीषण हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. वहीं एनएच-104 का हाल अब तक वहीं है, जो दशकों पूर्व था. शिवहर सांसद रमा देवी की पहल पर हाल के महीना में सड़क निर्माण एजेंसी ने कार्य शुरू तो कराया है, मगर रफ्तार से लगता नहीं है कि निकट भविष्य में निर्माण का कार्य पूर्ण हो सकेगा. उधर, एनएच-104 के सीतामढ़ी से लेकर नेपाल सीमा को जोड़ने वाली भिट्ठा मोड़ के बीच सालों पहले सड़क का निर्माण तो कराया गया. मगर इस रास्ता में पड़ने वाला दर्जनों पुल और पुलिया को पुराने हाल में छोड़ दिया गया, जो अब तक आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है. इस रास्ते में कई ऐसे डायवर्जन बनाए गए हैं, जहां मामूली बरसात के बाद ही वाहन चालकों के लिए आवागमन एक गंभीर चुनौती बन जाती है. ख़ासकर देश के अलग-अलग प्रांतों से पर्यटकों को लेकर प्रतिदिन आने वाली दर्जनों बसों के चालकों के लिए नेपाल के जनकपुर धाम तक आवागमन एक चुनौती बनी रहती है. निर्मित सड़क का हाल है कि धीरे-धीरे पुराने रूप में लौटने लगी है. मगर इसे कोई देखने को तैयार नहीं है. अब लोगों को इंतजार उस दिन का है, जब एनएच-77 और 104 पूर्ण रूप से दुरुस्त होगी. वाहनों का परिचालन बेरोक-टोक होगा. आवागमन में समय की बचत होगी. मगर यह तभी संभव हो पायेगा, जब स्थानीय जनप्रतिनिधि मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक पहल करने को आगे आएंगे. जाति व पार्टी के झंडा को विकास के हीत में जबतक किनारे नहीं रखा जायेगा, तब तक जनता की उम्मीदों को पूरा करना मुश्किल है.■

eeedbabk@bhauthiduniya.bom

गांव की सरकार को गीत की दवाई

चौथी दुनिया ब्यूरो

eeedback@chauthiduniya.com

पिछले दिनों संपूर्ण बिहार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. इसका मकसद पंचायत प्रतिनिधियों को इनके अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देना था. सरकारी निर्देश के आलोक में प्रशासनिक स्तर पर जोड़-शोर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. परंतु वहीं हुआ, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी. प्रशिक्षण से लौटने के बाद भी कई वार्ड सदस्यों को अपने कर्तव्य की समुचित जानकारी नहीं हो सकी. बताया जाता है कि इसके लिए दो स्तर पर लापरवाही हो सकती है. पहला यह कि प्रशासनिक स्तर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया. दूसरा यह कि पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में कोई ख़ास मतलब नहीं रखा है. अब कारण जो भी हों, मगर इतना तो साफ है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के पीछे सरकार की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है. वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर अनोखा अंदाज में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया गया है. सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड के रामपुर गंगोली स्थित गणेश सरस्वती सेवा संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में शिवहर प्रखंड के नव निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. गांव विकास मंच द्वारा द-हंगर

प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण अलग अंदाज में संपन्न हुआ. प्रोग्राम ऑफिसर शाहिना प्रवीण, द-हंगर प्रोजेक्ट पटना की स्टेट कॉ आर्डिनेटर रंजना कुमारी, इजाद की सचिव अख़्तरी बेगम के अलावा स्थानीय प्रशिक्षक शशिकला, रंभा कुमारी व रण विजय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को इनके अधिकार को कार्य करने की योजनाओं की समुचित जानकारी दी. गीत व संगीत के माहौल में महिला प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षक के बताये अधिकांश बातों को यूं ही याद करने में कामयाब रही. प्रतिनिधियों के उत्साह का आलम रहा कि 'अब त घास भूसा कर चाहे छोड़ द सैया, पंचायत जात बानी...; जैसे गीतों को गाकर रोल प्ले, विडियो शो व चार्ट प्रदर्शनी द्वारा पंचायती राज कानून की जानकारी वार्ड सदस्य, मुखिया, उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के अधिकार व कर्तव्य की जानकारी ली. वहीं तीस-तीस के दो समूह में प्रशिक्षण लेने वाली पिपराही प्रखंड की पंचायत प्रतिनिधियों ने वार्ड सभा व ग्राम सभा का समय, अध्यक्षता व कार्यकारिणी के बैठक समेत अन्य जानकारी लेती रही. प्रशिक्षण समापन के अवसर पर शिवहर जिला परिषद अध्यक्ष नीलम देवी, उपाध्यक्ष सुखलाल राम, समेत अन्य ने प्रशिक्षण में शामिल पंचायत प्रतिनिधियों की सजगता को सराहा. महिला प्रतिनिधियों ने 'दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब हीं जमाना बदलेगा... की लय से वातावरण में महिला सशक्तीकरण के अंदाज का प्रवाह कर दिया. गांव विकास मंच के नागेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि अब जरूरत है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों को उनका कार्य करने की हर स्तर पर स्वतंत्रता मिले. जब तक महिलाओं को अधिकार को सदुपयोग का मौका नहीं मिलेगा, तब तक बापू के पंचायती राज का सपना साकार नहीं हो सकेगा.■

नियमित दिनचर्या, दीर्घायू जीवन
शुभ दिपावली
सेहतनामा

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
डॉ. तरूण शरण (M.D. Medicine)
औषधालय, नवादा
सदर हॉस्पिटल के पास

नवादा के डॉ.तरूण शरण ने अपने दिए गये इन्टरव्यू में कम समय में लोगों के दीर्घायू होने के टीप्स बता दिये उन्होंने वर्तमान समय में लोगों के अर्थ के प्रति भाग दौड़ लगाने और उसके बाद टी.वी. मोबाईल आदि में अपना समय बिता देने वाले को मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्ति बताया। इस तरह के लोग अपनी दिनचर्या बिगाड़ लेते हैं और बीमारी को बुला लेते हैं। डॉ.शरण ने कहा पेसेंट दीर्घायू हों उसके लिए दवा के साथ-साथ दैनिक दिनचर्या सही करना जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य केवल ईश्वर का वरदान नहीं बल्कि आपके सकारात्मक प्रयास का फल होता है। सकारात्मक सोंच व्यवस्थित दिनचर्या और जागरूकता से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहता है। मानसिक स्वास्थ्य सही रखने के लिए डॉ. शरण ने बताया कि प्राणायाम, भावनात्मक नियंत्रण और ध्यान बहुत जरूरी है।

दीर्घायू जीवन के लिए व्यसन, तम्बाकू, और मादक पदार्थों को छोड़ना जरूरी है। डॉ. शरण ने बताया अनुशासित जीवनशैली, सकारात्मक दृष्टिकोण, संतुलन, संयम व पूजा पाठ को अपनाकर दीर्घायू जीवन जी सकते हैं। सुबह का मार्निंग वाक अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। उन्होंने बताया कि कम खायें, समय पर खायें, सही खायें 6 से आठ घंटे नींद लें और खुश रहें। ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

लखनऊ में बना लोकनायक की स्मृतियों को संजोने वाला नायाब संग्रहालय

जेपी कहीं मुक्त तो कहीं बंधक!

सूफी यायावर

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नायाब कदम उठाया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में 19 एकड़ में फैले जयप्रकाश नारायण संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे. सपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद यादव भी कार्यक्रम में शरीक थे. समाजवाद का संग्रहालय नाम से बने भवन में लोकनायक के संघर्ष को चित्रों और प्रदर्शकों के जरिए सहेजा गया है.

गोमती नदी के करीब बने इस संग्रहालय की डिजिटिल लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही महानायक अमिताभ बच्चन की आकर्षक आवाज में डॉक्युमेंट्री सुनाई देती है. चार ब्लॉकों में बंटा यह भवन 19 एकड़ में फैला हुआ है जिसे 'समाजवाद का संग्रहालय: जय प्रकाश नारायण विवेचना केन्द्र' नाम दिया गया है. संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य जेपी के जीवन और विचारधारा से आम आदमी को परिचित कराना और उन मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाना है, जिनके लिए जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष किया. इससे आम जन अपने जीवन में और समाज में कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं. संग्रहालय को चार क्षेत्रों समावेशन, चिंतन, मंथन और संगठन में विभाजित किया गया है. केन्द्र में प्रवेश करते ही समावेशन क्षेत्र लोगों को जयप्रकाश नारायण और देश के लिए उनके योगदान से परिचित कराता है. समावेशन क्षेत्र में जेपी से सम्बन्धित अधिकारिक जानकारी को इस तरह दर्शाया गया है कि लोगों के मन में उनके प्रेरक व्यक्तित्व को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है. यहां विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके जानकारी दी जाएगी. रोचक और मनोरंजक ढंग से दी गई जानकारी समझने में आसान होगी. चिंतन क्षेत्र में जेपी के जीवन के सबसे रोचक पहलुओं, खासकर उन प्रसंगों की जानकारी दी गई है, जिनके घटने के बाद ही आपातकाल की घोषणा की गई थी. इस दौरान समाजवाद के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए जेपी ने असीम साहस और आत्मबल का प्रदर्शन कर देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि यदि कोई आम इंसान ठान ले तो वह समाज के हित के लिए अकेला ही काफी है. इस प्रदर्शनी में प्रयोग की गई तस्वीरें यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके जीवन की उन स्मृतियों को लोग अपने मन में बसा लें.

संग्रहालय का मंथन क्षेत्र जेपी के जीवन की उन घटनाओं पर केंद्रित है, जो 1975 के उस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष के दौरान और उसके बाद घटी थी. मंथन क्षेत्र लोगों को यह अहसास भी दिलाएगा कि जीवन में लक्ष्य के साथ-साथ उसे पाने के उचित मार्ग का चयन करना भी आवश्यक है. सीढ़ी के घूमने की गति आपातकाल की घटनाओं की गति और उसके आकस्मिक स्वरूप से मेल खाती है. आपातकाल के दौरान जेल में जेपी ने अपने स्वास्थ्य और देश की हालत दोनों साथ-साथ खराब होते देखी. जेपी द्वारा जेल में किए गए चिंतन से यह ज्ञान होता है कि असीम दुख और प्रताड़नाओं के बावजूद जेपी हार मानने वालों में से नहीं थे. उन्होंने बिखरे टुकड़ों को समेट कर नई ऊर्जा और लक्ष्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया.

संगठन क्षेत्र संग्रहालय के अनुभव का अंतिम भाग है. विहंगम दृश्यों से भरी इसकी सीढ़ियां व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विचारों और अनुभवों के समावेश के लक्ष्य से संकल्पित की गई हैं. विचारों और अवधारणाओं को संक्षिप्त में बताने और उसे आत्मसात करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है. खुली जगह में स्थापित यह क्षेत्र विचारों के विस्तार के लिए अनुकूल है. संग्रहालय के गहन अनुभव को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देने के इरादे से इसे बनाया गया है. इसके अलावा, समाजवाद का संग्रहालय: जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र में पाठन क्षेत्र, पुस्तकालय, संग्रहालय सौंध, प्रदर्शनी क्षेत्र और खुला रंगमंच का निर्माण किया गया है. साथ ही करीब दो हजार लोगों की क्षमता का प्रेक्षागृह, करीब एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला दो सेमिनार हॉल, डॉरमेट्री, हेल्थ सेंटर व जिम्नेजियम, ओलम्पिक साइज का स्वीमिंग पूल, डायविंग पूल, किड्स पूल, लॉन टेनिस कोर्ट और मल्टीपरपस कोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है. यह कार्य भी अन्तिम चरण में ही है. यहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है.

देश के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि जयप्रकाश नारायण एक महान नेता और विचारक थे. देश की आजादी के साथ-साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया. देश की आजादी के लिए वे कई बार जेल गए. उन्होंने आजाद भारत में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया. अपने सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार व अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे लोकतंत्र की बहाली हुई. उन्होंने राजनीति में नौजवानों को प्रभावित कर एक नई दिशा दी. उनके प्रयासों की बदौलत भारतीय राजनीति की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव आया था. लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रेरक व्यक्तित्व व कृतित्व तथा इतिहास में उनके योगदान के मद्देनजर गोमती नगर के विपिनखंड में स्थापित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना पर 844 करोड़ रुपये का खर्च आया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जेपी की संस्था पर अवैध कब्जा मुक्त कराने में सरकार ढीली

एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृतियों को संजोने के लिए संग्रहालय की स्थापना कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जेपी के ही बनाए हुए संस्थान को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में ढिलाई बरत रही है. वाराणसी में जेपी के बनवाए गांधी विद्या संस्थान को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का तो बाकायदा आंदोलन चल रही है, जिसमें देश और दुनियाभर के गांधीवादी शरीक हैं. बनारस के राजघाट स्थित गांधी विद्या संस्थान (दि गांधियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्टडीज) को मुक्त कराने के लिए पिछले दिनों गांधी और जेपीवादियों ने लखनऊ गांधी प्रतिमा पर धरना भी दिया. इसमें ग्रस्थात गांधीवादी चिंतक 92 वर्षीय प्रो. रामजी सिंह समेत कई लोग शरीक थे. गांधी विद्या संस्थान पर गत कई वर्षों से अवैध कब्ज़ा है. मुख्य भवन में संस्कृत की अवैध पाठशाला चल रही है. संस्था से निष्कासित कर्मचारी एक लाख रुपये महीना किराया वसूल रहा है. जेपी द्वारा बनाई गई संस्था उन लोगों के कब्जे में है जो गांधी और जयप्रकाश के विचारों के विरोधी हैं. ■

रावत पर राजी कांग्रेस, खंडूरी पर खंडित भाजपा

राजकुमार शर्मा

प्रगतिशील डेमोक्रैटिक फ्रंट से नाता तोड़ने की मांग उठा कर कांग्रेस ने हरीश रावत सरकार को दुविधा में डाल दिया है. पीडीएफ की भूमिका को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मुखिया किशोर उपाध्याय की तरफ से सवाल खड़ा करने से सरकार और संगठन की बढ़ती खाई उजागर हुई है. मुख्यमंत्री रावत ने कांग्रेस हाईकमान के पाले में गेंद डालते हुए इस मसले से पल्ला झाड़ कर पीडीएफ का साथ न छोड़ने का संकेत दे दिया है.

उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के गठन से लेकर हरीश सरकार पर आए संकट के समय तक राज्य के पांच निर्दलीय विधायकों के प्रगतिशील डेमोक्रैटिक फ्रंट ने कांग्रेस का साथ दिया, यह एक राजनीतिक मिसाल है. राज्य में थोड़े अंतर से सरकार के गठन का पेंच फंसा था, उस समय प्रगतिशील डेमोक्रैटिक फ्रंट के फैसले से भाजपा की चूलें हिल गईं. फ्रंट कांग्रेस का साथ दे रहा है और तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद हरीश सरकार का बनी हुई है. उत्तराखंड में कांग्रेस में बगावत करा कर रावत सरकार को बेदखल करने का जो राजनीतिक कुचक्र रचा गया था, वह नाकाम साबित हुआ. इसी का नतीजा है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी हरीश रावत को सरकार के गठन से ले कर संचालन तक की पूरी छूट दे दी. लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय इस तालमेल की जड़ में मट्ठा डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. जबकि कांग्रेस आलाकमान मिशन 2017 रावत के नेतृत्व में ही चुनावी पताका लहराने की तैयारियां कर रहा है. संगठन के प्रदेश मुखिया द्वारा उठाया गया सवाल भी एक बगावत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भले ही यह कहते हों कि हरीश रावत के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उनका तौर-तरीका इस बयान के ठीक उलट है.

हरीश रावत

भुवन चंद्र खंडूरी

उत्तराखंड राज्य सवर्ण बहुल है. इस राज्य में सत्ता पाने के लिए तमाम राजनीतिक दल सत्ता-संगठन में एक पद ब्राह्मण तो दूसरा राजपूत को सौंप कर मैदान मारने की रणनीति पर कामयाबी प्राप्त करते रहे हैं. इसी फार्मूले पर कांग्रेस भी चल रही है. रावत को पछाड़ने के लिए भाजपा ब्राह्मण मतदाताओं को कांग्रेस से बिदकाने का काम कर रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मणों में मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं.

दूसरी तरफ 'खंडूरी है जरूरी' की मांग से भाजपा हाईकमान भी परेशान है. कांग्रेस मुक्त हिमालय के भाजपाई संकल्प को कांग्रेस से गए नेता ही पलीता लगा रहे हैं. कांग्रेस के 'विभीषणों' के दम पर मिशन 2017 में उत्तराखंड फतह का भाजपाई सपना अंतरकलह के कारण परवान नहीं चढ़ पा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बल पर मुख्यमंत्री की कुर्सी थामे रहने वाले हरीश रावत को सत्ता से बेदखल करना भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है. उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में सीधा मुकाबला हरीश रावत बनाम नरेन्द्र मोदी होने जा रहा है. जमीनी स्तर पर एक बार फिर उठने लगी 'खंडूरी है जरूरी' की मांग से भाजपा हाईकमान परेशान है. मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भी यह साबित कर रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता कायम है और उनमें अभी भी काफी दम है. भाजपाइयों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि कांग्रेस जब मुख्यमंत्री के बतौर रावत के चेहरे को आगे लेकर चल रही है तो भाजपा क्यों नहीं! लेकिन भाजपा नेतृत्व इसे लेकर असमंजस में है. मुख्यमंत्री पेश करने के सवाल पर भाजपा हाईकमान दो खेमों में बंटा दिखता है. एक खेमा अमित शाह के साथ है, जो संघ के निर्देश पर प्रदेश में कोई संघ-पृष्ठभूमि के युवा चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जैसे नेता हैं, जो जनरल खंडूरी के हिमायती हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में गए सतपाल महाराज, डॉ. हरक सिंह समेत कई नेता भी अपना दावा यदा-कदा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ठोकते रहते हैं. उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहे 'उत्तराखंड क्रांति दल' (उक्रांद) के नेताओं की आज उतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई. इस वजह से भी भाजपा और कांग्रेस निश्चिंत हैं. योग गुरु रामदेव हरिद्वार के सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के पक्ष में खड़े हैं और एक अलग समीकरण बना रहे हैं. जनरल को आगे करने की ख़बर ने भगत सिंह कोश्यारी को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तक पहुंचा दिया. कोश्यारी की यह घोषणा हालांकि एक राजनीतिक शिगूफा ही मानी जा रही है.

भाजपा की पिछली कार्यसमिति की बैठक में 'थिंक टूगेदर, वर्क टूगेदर' का सूत्रवाक्य तो रचा गया लेकिन अधिकांश प्रतिनिधि आलाकमान की सोच से अलग 'खंडूरी है जरूरी' के नारे और विचार के ही साथ खड़ा दिखा. भाजपा आलाकमान खंडूरी को उम्र की दहलीज वाले फार्मूले पर रख कर किनारे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कुछ और चाहते हैं, यह भाजपा के सामने मुश्किल आने ही वाली है. भाजपा का प्रतिबद्ध और ईमानदार काडर हरीश रावत को धूल चटाने के लिए अगली पंक्ति पर सेनापति के रूप में जनरल खंडूरी को ही देखना चाहता है. उत्तराखंड भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के लगभग 750 प्रतिनिधियों ने 'थिंक टूगेदर, वर्क टूगेदर' का संकल्प लेते हुए खंडूरी के समर्थन का ही संकल्प लिया. कार्यसमिति में यह साफ तौर पर उभर कर सामने आया कि कांग्रेस से आए 'विभीषणों' या दागदार निशंक के प्रति भाजपा आलाकमान ने रुझान दिखाया तो पर्वतीय प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होने के बजाय भाजपा ही मुक्त हो जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी के अघोषित विभाजन की चर्चा गरम, सियासी कुचक्र चरम

मुलायम थामें कमान इस पर घमासान

सांगठनिक अधिकारों से मुक्त किए जाने से अखिलेश नाराज

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर आर-पार के युद्ध का माहौल है. शिवपाल बनाम अखिलेश विवाद का प्रति-उत्पाद यह है कि समाजवादी पार्टी दो खाने में बंटी हुई साफ-साफ दिख रही है. अखिलेश के समर्थक एक तरफ और शिवपाल के समर्थक दूसरी तरफ. अब तो पार्टी दफ्तर भी दो तरफ है. एक तरफ वाले दफ्तर में शिवपाल और उनके लोग तो दूसरे दफ्तर में अखिलेश और उनके लोग. अखिलेश के समर्थकों को शिवपाल पार्टी से बाहर निकाल चुके, लेकिन वे अखिलेश के साथ बने हुए हैं और समानान्तर दफ्तर में बाकायदा विराजमान हो रहे हैं. दोनों ही खाने समाजवादी पार्टी के हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं. शिवपाल यादव अखिलेश के समर्थकों को संगठन से बाहर करने पर तुले हुए हैं. अखिलेश समर्थकों को चुन-चुन कर संगठन के विभिन्न पदों से हटाए जाने का सिलसिला जारी है. अब स्पष्ट तौर पर यह दिखने लगा है कि कमान संभालने के लिए मुलायम पर जोर डाला जा रहा है. इससे असहमत अखिलेश सार्वजनिक सभाओं में मुलायम के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता यह तर्क देते हैं कि मुलायम के कमान संभाल लेने से पार्टी टूटने से बच जाएगी. उनका मानना है कि इस पर अखिलेश चुप रह जाएंगे. लेकिन कुछ नेता इस तर्क से सहमत नहीं दिखते. उनका मानना है कि 2012 का चुनाव जीतने का श्रेय मिलने के बाद अखिलेश अब एक स्वतंत्र राजनीतिक के बतौर खुद को स्थापित करने की मंशा रखते हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव में वे किसी भी कीमत पर कमान अपने हाथ में ही रखना चाहेंगे, ताकि चुनाव उनके नेतृत्व और चेहरे पर लड़ा जाए और वे फिर मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता पर वापस लौटें.

सपा के नए सिपहसालारों में से एक ने कहा कि मुलायम के कमान संभालने से सत्ता के खिलाफ पड़ने वाले (एंटी-इंकमबेंसी) वोट से पार्टी बच जाएगी. स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके खेमे के नेता-मंत्री इससे असहमत हैं और इसे वे तिकड़म का हिस्सा मानते हैं. प्रभावशाली चुनावी चेहरे के अलावा पार्टी की नीतियों को लेकर भी नेतृत्व के स्तर पर भीषण अंतरविरोध है. असरकारक नेतृत्व के सवाल पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के पक्ष में खड़े हैं. लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव अखिलेश यादव को ही अधिक असरकारक चेहरा मानते हैं. नीतियों को लेकर पार्टी में टकराव की स्थिति यह है कि नए बने प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव माफियाओं अपराधियों और घोटालेबाजों को चुनावी टिकट देने से कोई परहेज नहीं कर रहे तो अखिलेश ऐसे तत्वों को टिकट देने के खिलाफ खड़े हैं. नीतिगत स्टैंड को लेकर प्रदेश के आम लोग अखिलेश के प्रति समर्थन जता रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुलायम का चेहरा सामने रख कर विधानसभा चुनाव में उतरने का विचार इसलिए भी चल रहा है क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव खास होगा और सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का मानक बनेगा. लेकिन सपा में चल रहे विवाद के कारण पार्टी की जो सार्वजनिक किरकिरी हुई है, उसे लेकर भी पार्टी के नेता चिंतित हैं.

समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुलायम का चेहरा सामने रख कर विधानसभा चुनाव में उतरने का विचार इसलिए भी चल रहा है क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव खास होगा और सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का मानक बनेगा. लेकिन सपा में चल रहे विवाद के कारण पार्टी की जो सार्वजनिक किरकिरी हुई है, उसे लेकर भी पार्टी के नेता चिंतित हैं. उधर सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वे सपा के इस अंदरूनी विवाद का फायदा उठाएं. बसपा और भाजपा खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है. इस विवाद के कारण भाजपा के चुनावी चेहरे का मुद्दा चर्चा से फिलहाल बाहर चला गया है. हालांकि संघ ने अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से भाजपा नेताओं को फिर से चेताया है कि अगर पार्टी ने कोई प्रभावशाली नेता (यूपी निवासी) उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामने नहीं रखा तो पार्टी को बिहार की तरह विपरीत परिणाम देखने पड़ सकते हैं.

बहरहाल, समाजवादी पार्टी में संभावित विभाजन को रोकने के लिए मुलायम को कमान सौंपने की कवायद में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह भी जीजान से जुटे हैं. अमर सिंह की रणनीति है कि उनकी उपेक्षा करने वाले अखिलेश यादव और अखिलेश का साथ देने वाले धुर अमर विरोधी प्रो. रामगोपाल को किनारे लगा कर वे अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल कर लें. लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी में यह बात उठने लगी थी कि मुलायम सिंह अखिलेश को हटा कर सत्ता पर खुद काबिज हों और 2017 का चुनाव मुलायम के नेतृत्व में ही लड़ा जाए. लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद मुलायम कई बार सार्वजनिक मंचों से यह बोल गए हैं कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को ऐसी हार देखनी पड़ी. अखिलेश सरकार के खिलाफ भी मुलायम की बोली क्रमशः तल्ख होती गई. पंचायत चुनावों में बनाई रणनीतियों के कारण सपा की भारी जीत के बाद ही शिवपाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया था. मुलायम को बस सटीक वक्त का इंतजार था. आने वाले विधानसभा चुनाव में मुलायम अकेले अखिलेश के बूते सारा कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे. अखिलेश की युवा टीम सांगठनिक नतीजे देने में कामयाब साबित नहीं हुई, इसे लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के मन में नाराजगी थी. आपको याद ही होगा कि कुछ अर्सा पहले बेनी प्रसाद वर्मा ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सत्ता लेकर मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए. बेनी ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यूपी के मंत्री और विधायक विकास कार्य कराने में कमीशन ले रहे हैं. ऐसे में यदि सपा को अपनी सरकार बचानी है तो इन सब पर काबू पाने की जरूरत है. बेनी ने कहा था कि हमें यूपी में भाजपा को आने से रोकना है इसलिए हम चाहते हैं कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, रिश्वत व कमीशनखोरी व बेलगाम अफसरों पर शिकंजा कसें. वे खुद प्रदेश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लें, इसमें हम उनका पूरा साथ देंगे. जिस समय बेनी ने यह बातें कही थी, उस समय वे कांग्रेस में थे. लेकिन इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में आ गए और राज्यसभा के सदस्य भी बना दिए गए. उस समय जो बेनी बोल रहे थे, बाद में शिवपाल भी वही बोलने लगे.

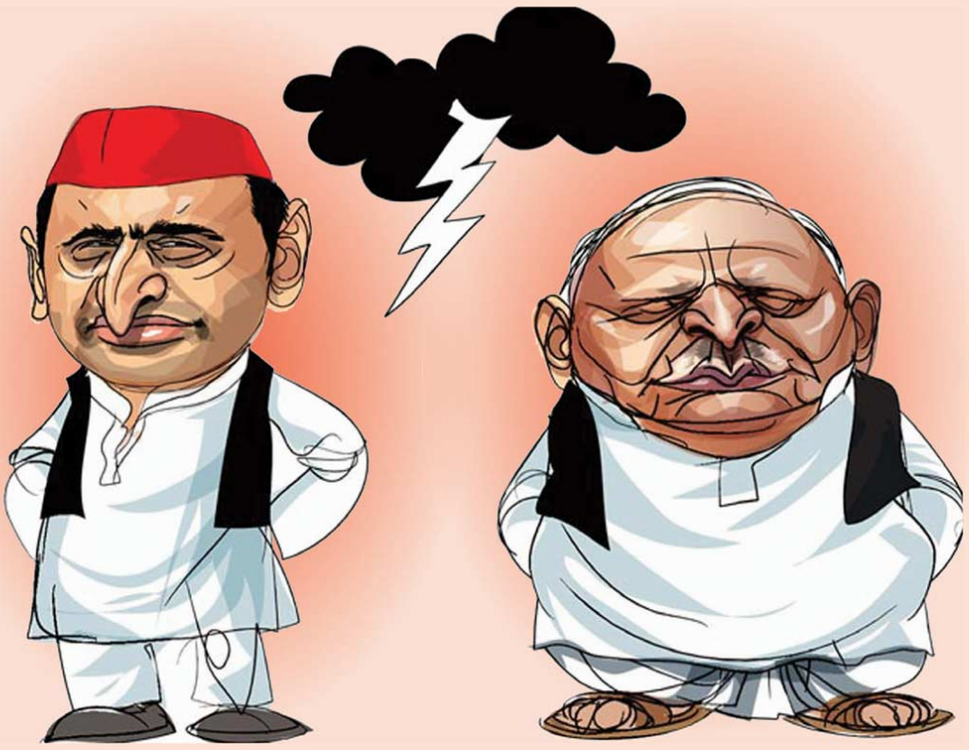

अब आमना-सामना होने से भी बचने लगे मुलायम-अखिलेश

समाजवादी पार्टी का मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि अब अखिलेश या मुलायम सार्वजनिक मंचों पर आमना-सामना होने से भी बचने लगे हैं. नए सचिवालय से उद्घाटन से लेकर जयप्रकाश नारायण संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर अखिलेश मुलायम से बचते दिखे. पिछले दिनों लोहिया पुण्यतिथि के अवसर पर तो अखिलेश बिना भाषण दिए ही चले गए. अखिलेश के जाने के बाद मुलायम आए. अखिलेश यादव सुबह साढ़े दस बजे लोहिया पार्क पहुंचे और लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर चले गए. यह पहला मौका था जब लोहिया की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री का भाषण नहीं हुआ. इसी तरह सपा के दो समानान्तर मुख्यालय, अब किसी से छिपी बात नहीं रही. विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी का मुख्यालय अब शिवपाल और उनके समर्थकों के कब्जे में है और बंदरिया बाग स्थित जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट अखिलेश और उनके समर्थकों का मुख्यालय बन गया है. ■

अखिलेश-शिवपाल विवाद पर सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुलायम ने शिवपाल को आगे करके क्रमशः अखिलेश की पकड़ कमजोर की है. सरकार पर खुला प्रहार, मंत्रियों के काम-काज पर आपत्ति, कौमी एकता दल के विलय को लेकर नाटक, मंत्रियों की बर्खास्तगी फिर वापसी, अखिलेश समर्थकों का निष्कासन, वापसी, फिर निष्कासन, शिवपाल के इस्तीफे का प्रहसन और उस पर मुलायम का खुला ऐलान और आखिरकार अखिलेश का पार्टी अध्यक्ष पद से निष्कासन, यह सब नियोजित है. बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से धीरे-धीरे अखिलेश के हाथ से संगठन-शक्ति छीन ली गई. अब उनसे सत्ता हथियाने की तैयारी है. उक्त नेता ने कहा कि युवाओं का अखिलेश को समर्थन मिलने के दावे को कमजोर करने के इरादे से मुलायम ने अब युवाओं की उत्पादकता पर प्रहार करना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों लोहिया पुण्यतिथि के अवसर पर भी मुलायम ने कहा कि युवा सिर्फ नारे लगाते हैं, उनमें कोई उत्पादकता नहीं. केवल नारे लगाने से राजनीति थोड़े ही चलती है. अखिलेश को कमजोर करने के अभियान को जारी रखते हुए शिवपाल यादव ने पिछले दिनों सपा के शाश्वत समर्थक व अखिलेश को मानने वाले बुजुर्ग नेता एसआरएस यादव को पार्टी के सचिव पद से बेदखल कर दिया. सपाई कहते हैं कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाले जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का सदस्य बनाए जाने के कारण एसआरएस यादव को सचिव पद से हटा दिया गया. अब उनकी जगह वीरेंद्र सिंह को सचिव बनाया गया है. प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपनी करीबी सुरभि शुक्ला को भी पार्टी में सचिव बना दिया है. सुरभि शुक्ला आवास विकास परिषद में उपाध्यक्ष हैं और सियासी कृपा से उनके पति डॉ. संदीप शुक्ला भी राजकीय निर्माण निगम के सलाहकार हैं. अखिलेश के करीबी गोपाल अग्रवाल को भी समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को अध्यक्ष बना दिया गया है. इस तरह शिवपाल ने सपा के प्रदेश संगठन पर अपना कब्जा जमा लिया है. इसके पहले उन्होंने 81 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर अखिलेश को बाहर कर दिया और उनके समर्थकों को विभिन्न पदों से बेदखल कर दिया. चुनाव में टिकट बंटवारे के अधिकार से वंचित कर अखिलेश को पूर्ण रूप से हाशिए पर रख देने की तैयारी पर अब काम चल रहा है.

अखिलेश के पुरजोर विरोध के बावजूद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय करा ही दिया गया. अब सार्वजनिक बयान भी आने लगे हैं कि मुख्तार अंसारी सपा के सिम्बल पर चुनाव लड़ेंगे. शिवपाल ने कुख्यात अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हत्यारोपी अमनमणि त्रिपाठी और एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर अपनी प्राथमिकता दिखाई. दागी और अपराधियों को टिकट दिए जाने से कुपित अखिलेश यहां तक बोल गए कि उन्होंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए हैं, लेकिन उनके हाथ में तुरुप का पत्ता है. कौमी एकता दल के विलय से लेकर दागी लोगों को टिकट दिए जाने या पार्टी पदाधिकारियों को बदले जाने के सभी निर्णयों के पीछे मुलायम सिंह यादव का आदेश है. शिवपाल कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि कौमी एकता दल के विलय से लेकर अन्य फैसले तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से सीधे निर्देश प्राप्त कर लिए जा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पहचान के संकट से जूझता कला केंद्र

अनंत विजय

दिल्ली में इस बात को लेकर अर्से से शोर मच रहा है कि यहां साहित्य और कला प्रेमियों के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है. कनॉट प्लेस में कॉफी शॉप बंद होने के बाद से इस तरह की मांग उठती रही है कि विमर्श का एक अड्डा होना चाहिए, जहां बैठकर साहित्यकार और कलाकार बहस कर सकें. दिल्ली में पुस्तकालयों को लेकर भी खासी चर्चा होती रही है. जब भी इस तरह की चर्चा होती है, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के अलावा हरदयाल लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का नाम आता है. इन चर्चाओं के बीच दिल्ली के दिल में स्थित एक कैंपस में एक और लाइब्रेरी है, जिसका ना तो कभी जिक्र होता है और ना ही इसके बारे में किसी तरह का प्रचार होता आया है. ये पुस्तकालय है जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का. इस पुस्तकालय में ढाई लाख किताबें हैं, जो कि साहित्य, कला, संस्कृति समेत विभिन्न विषयों पर हैं. इस बड़ी लाइब्रेरी के बारे में दिल्ली के साहित्यप्रेमियों को जरा कम ही पता है. सालभर का शुल्क भी महज पांच सौ रुपए है. इसके अलावा इस पुस्तकालय में नियमित रूप से लेखकों का रचना पाठ भी होता है. होता सब कुछ है यहां, लेकिन वो साहित्य प्रेमियों तक ना पहुंचकर एक खास वर्ग के लोगों को ही इसकी जानकारी दी जाती है या उनको मिल पाती है. रचना पाठ के बारे में कभी किसी अखबार में कुछ छपा हो, याद नहीं पड़ता. इतनी समृद्ध लाइब्रेरी के बारे में कभी किसी अखबार ने फीचर किया होगा, स्मरण नहीं आता. दरअसल दिल्ली के दिल में छब्बीस एकड़ भूमि पर बने इस राष्ट्रीय कला केंद्र के पास इतना बड़ा खजाना मौजूद है, जो कि दिल्ली के साहित्य कला प्रेमियों को समृद्ध कर सकता है, लेकिन अबतक इस खजाने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही थी. इस केंद्र को एक खास किस्म के अभिजात्य से जोड़कर रखा गया था, ताकि यहां आम पाठकों का प्रवेश ही संभव ना हो सके. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके नाम से स्थापित इस कला केंद्र में लाइब्रेरी तो है ही, यहां करीब दो लाख कृतियों की पांडुलिपियां भी सहेज कर रखी गई हैं, जो अपने हमारी समृद्ध लेखकीय परंपरा का दस्तावेज है. अबतक इस कला केंद्र के प्रशासन से जुड़े लोगों ने बहुत काम किया. कई कलाकारों के पूरे संग्रह खरीद लिए, कई लेखकों के पूरे संग्रह को संग्रहित करवा दिया, कई बड़े आयोजन कर लिए, लेकिन एक जो काम नहीं किया, वो ये कि इस केंद्र को आम साहित्य और कला प्रेमियों से नहीं जोड़ा. इस कला केंद्र की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, उससे भी ये संस्था भटकती रही या यों कह सकते हैं कि उस राह पर मजबूती से आगे नहीं बढ़ी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बेवसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक उन्नीस सौ पचासी में इंदिरा जी के जन्मदिन यानि उन्नीस नवंबर को इसकी कल्पना की गई और चौबीस मार्च उन्नीस सौ सतासी को इसकी शुरुआत की गई. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट बनाया गया जिसमें राजीव गांधी, आर वेंकटरमण, पीवी नरसिंहाराव, पुपुल जयकर, एचवाई शारदा प्रसाद और कपिला वात्स्यायन शामिल थे. ये इतने बड़े नाम हैं, जो किसी भी संस्था के लिए उसके मजबूती के परिचायक हो सकते हैं. यह संस्था जब खबरों में आई थी, तो वो विवाद को लेकर जब इसके ट्रस्टियों को बदले जाने पर और आजीवन ट्रस्टी नियुक्त करने पर विवाद हुआ था. तभी देशभर के लोगों ने जाना था कि दिल्ली में एक कला केंद्र हैं, जहां के ट्रस्टी का पद कुछ इतना बड़ा होता है कि उसको लेकर सरकार और एक खास परिवार के बीच तलवार भी खिंच सकती है.

इस केंद्र की परिकल्पना कला के क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षिक उद्यम और प्रचार-प्रसार

अब अगर किसी संस्थान के पास दो लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं तो उसके संरक्षण की चिंता तो करनी ही होगी. इंदिरा गांधी कला केंद्र के पास जितने संसाधन हैं. उसका सार्थक उपयोग इस कला केंद्र को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए नाकाफी हो सकते हैं लेकिन देश में और कम से कम दिल्ली में इस कला केंद्र को एक अहम पहचान दिलाने के लिए तो काफी हैं. दिल्ली में इतनी बड़ी जगह और उसका उपयोग नई टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

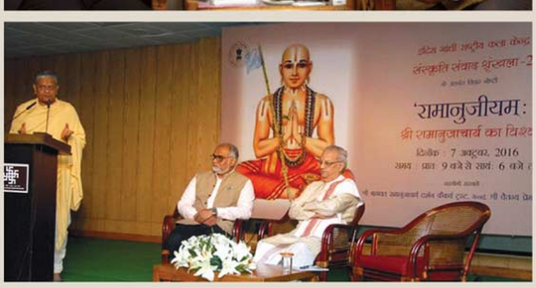

करने वाली एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी. कला का दायरा काफी विस्तृत रखा गया था और उसमें नृविज्ञान से लेकर पुरातत्व तक को इसमें शामिल किया गया था. लेकिन इस संस्था के कर्ता-धर्ताओं ने इस संस्था को पता नहीं किस रास्ते पर चलाने का फैसला किया कि ये आम आदमी से दूर होती चली गई और अपनी स्थापना के उद्देश्यों से लगभग भटक कर कुछ लोगों का अरण्य बनकर रह गई. इस संस्था ने कला के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान किए हों, उसको ना तो प्रचारित किया और ना ही उसके बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके. नतीजा यह हुआ कि जो भी शोध या अनुसंधान हुए, वो चंद लोगों तक ही पहुंच कर रह गए या फिर कला केंद्र के कमरों में बंद होकर रह गए. हाल में वरिष्ठ पत्रकार रामबहादुर राय को इस संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया था. उस वक्त काफी हो हल्ला मचा था और उसके बाद जब नामवर सिंह के 90 साल पूरे होने पर दिनभर का आयोजन हुआ था, तब भी एक खास वर्ग के लोगों ने शोर मचाया. उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि अब तक इस संस्था को अभिजात्य बनाकर रखा गया था, तब भी एक खास वर्ग के लोगों ने शोर मचाया. उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि अब तक इस संस्था को अभिजात्य बनाकर रखा गया था तो क्यों नहीं किसी तरह का कोई शोरगुल मचाया. क्यों नहीं किसी विचारधारा के ध्वजवाहक ने ये सवाल उठाया कि ये संस्था अपने उद्देश्यों से क्यों भटक गई. सवाल तो नामवर सिंह के जन्मदिन के बाद के आयोजनों पर भी नहीं उठाए गए.

दरअसल, अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदलाव की बयार बहती दिखाई दे रही है. सदस्य सचिव सचिदानंद जोशी के मुताबिक उनकी प्राथमिकता में संस्था को लोगों तक पहुंचाने और इसके कामों से लोगों को जोड़ने की है और वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से ही काम कर रहे हैं. क्या ये बात कल्पना से परे नहीं है कि दिल्ली के दिल में स्थित इस संस्था की लाइब्रेरी के सिर्फ 130 सदस्य थे. वो भी तब, जब इसका सालाना शुल्क सिर्फ 500 रुपए है. अब नई व्यवस्था में इस पुस्तकालय के दरवाजे खुले हैं तो सदस्य बढ़ने लगे हैं. कला केंद्र के पास इतनी अनूठी चीजें हैं जिसको प्रदर्शित करना शुरू किया गया है. अभी हाल ही में राजा दीनदयाल, जिन्हें भारत में फोटोग्राफी का जनक माना जाता है उनसे जुड़ी सारी चीजें एक गैलरी बानकर प्रदर्शित की गई है. राजा दीन दयाल मेरठ के पास 1844 में जन्मे थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंदौर चले गए थे. वहां उन्हें इंदौर के शासक महाराज टुकोजी द्वितीय ने संरक्षण दिया और उनको स्टूडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. राजा दीन दयाल को 1885 में वायसराय का ऑफिसियल फोटोग्राफर नियुक्त कर दिया गया और दो साल बाद उनको क्वीन विक्टोरिया की सेवा करने का मौका मिला. यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजा दीन दयाल से जुड़ी चीजें कला केंद्र में मौजूद थी, लेकिन उनको गोदाम में रख दिया गया था. अब उसकी प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिल रहा है. उनके कैमरे को देखकर लगता है कि उस जमाने में फोटोग्राफी कितनी मुश्किल रही होगी या फोटोग्राफी की कला तो उस वक्त ही थी जब मशीनों का साथ फोटोग्राफर को नहीं मिलता था.

शोध और शैक्षणिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अब इस संस्थान को छात्रों से जोड़ने की योजना भी बन रही है. सांस्कृतिक समझ को विकसित करने के लिए कल्चरल इंफोमैटिक्स कोर्स शुरू करने जा रही है जिसे एआईसीटीई से मान्यता भी मिल चुकी है. इस कोर्स के अलावा बौद्ध स्टडीज पर भी डिप्लोमा के माध्यम से छात्रों को जोड़ने की योजना है. इस कला केंद्र के पास एक अहम काम संरक्षण और पुनर्स्थापना का भी है. नई पीढ़ी के छात्रों को इस काम से जोड़ना बेहद श्रमसाध्य कार्य है, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संरक्षण और पुनर्स्थापना की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी. अब अगर किसी संस्थान के पास दो लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं तो उसके संरक्षण की चिंता तो करनी ही होगी. इंदिरा गांधी कला केंद्र के पास जितने संसाधन हैं. उसका सार्थक उपयोग इस कला केंद्र को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए नाकाफी हो सकते हैं, लेकिन देश में और कम से कम दिल्ली में इस कला केंद्र को एक अहम पहचान दिलाने के लिए तो काफी है. दिल्ली में इतनी बड़ी जगह और उसका उपयोग नई टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. अगर इस संस्था को लोगों से जोड़ पाने की चुनौती कामयाब होती है तो कला के हित में होगा. ■

(लेखक IBNT से जुड़े हैं)

anant.vijay@gmail.com

निर्मली

परिचय

आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में इसका वर्णन प्राप्त होता है. अति प्राचीन काल से जल शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. जल से भरे हुए पात्र में इसे थोड़ा घीसकर डालने से जल की समस्त गन्दगी नीचे बैठ जाती है. जिससे जल निर्मल या स्वच्छ हो जाता है. इसलिए इसे निर्मली कहते हैं. मुख्यतः भारत तथा श्रीलका में पाया जाता है. भारत में यह पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के पर्णपाती वनों में 1200 मीटर की उंचाई तक, मध्य भारत, कोंकण एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **नेत्र रोग-** सिर्फ सेंधानमक के साथ अथवा सेंधानमक तथा मधु के साथ निर्मली का अज्जन बनाकर आंखों में लगाने से नेत्रगत अर्नुनरोग (Subconjunctival haemorrhage) में लाभ होता है.
- निर्मली फल को मधु के साथ पीसकर, थोड़ा-सा कर्पूर मिलाकर नियमित अंजन करने से नेत्र निर्मल एवं दृष्टि प्रखर होती है.
- लालचंदन, पिप्पली, हल्दी तथा निर्मली बीज को जल में पीसकर वर्ती बनाकर, इस वर्ती को घिसकर अंजन करने से सभी प्रकार के नेत्ररोगों में लाभ होता है.
- निर्मली के बीजों को पीसकर उसमें थोड़ा-सा कपूर मिलाकर नेत्र के बाहर चारों ओर लगाने से नेत्रशूल में लाभ होता है.
- निर्मली-बीज को पानी में पीसकर उसमें थोड़ा सा सेंधानमक मिलाकर आंखों के बाहर लगाने से नेत्रशूल तथा नेत्रदाह (आंखों की जलन) का शमन होता है.
- **खांसी-** एक निर्मली के फल का गूदा निकालकर उसमें शहद मिलाकर चटाने से सूखी खांसी मिटती है.
- निर्मली त्वक् का चूर्ण बनाकर उसमें नींबू स्वरस मिलाकर, एक ग्राम की मात्रा में सेवन करने से हैजा में लाभ होता है.
- निर्मली के बीजों को पानी में पीसकर नाभि के आस-पास लेप करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं.
- निर्मली के एक बीज को पीसकर, तक्र में मिलाकर 5 दिनों तक पिलाने से बहुत पुराने अतिसार, जो किसी भी औषधि के प्रयोग करने से ठीक न हो, तो उनमें लाभ होता है.
- निर्मली के बीज को पीसकर शहद में मिलाकर खिलाने से प्रमेह में लाभ होता है.
- **मूत्र विकार-** निर्मली के दो बीजों को पानी में पीसकर, दही मिलाकर, चीनी मिट्टी के बर्तन में रखकर रात भर पउ रहने दें, प्रातः इसे निकालकर सेवन कर लें. इस प्रकार सात दिनों तक इसका सेवन करने से तथा पथ्य में दही चावल खाने से पेशाब की जलन तथा पेशाब के साथ खून आना बन्द हो जाता है.
- संग्रिशूल- निर्मली मूल को तेल में डालकर पकाकर, फिर छानकर मालिश करने से जोड़ों की वेदना का शमन होता है.
- निर्मली पत्रों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव का शोधन होता है तथा घाव जल्दी भर जाता है.
- निर्मली मूल को पीसकर लगाने से कुष्ठ आदि त्वचा रोगों में लाभ होता है.
- निर्मली फल सत्त से नस्य, अंजन तथा कर्णपूरण करने से अपस्मार में लाभ होता है.
- निर्मली फल को घिस कर वृश्चिक दंशस्थान पर लेप करने से दंशजन्य वेदना, शोथ आदि प्रभावों का शमन होता है. ■

प्रयोज्यांग : बीज, मूल एवं फल.

मात्रा : चूर्ण एक से तीन ग्राम. वमनार्थ छः ग्राम. क्वाथ 10-30 मिली अथवा चिकित्सक के परामर्शानुसार.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

भक्तों की सत्यनिष्ठा

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

श्री शिरडी साईं बाबा ने अपने एक भक्त को जो कि उस समय एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहा था, बताया था कि उसको व्यक्तिगत और कर्मक्षेत्र में सत्यनिष्ठा से आचरण करना चाहिए. यहां पर बाबा के द्वारा 'सत्यनिष्ठा' शब्द प्रयोग करने का तात्पर्य यह था कि हर व्यक्ति को उच्च नैतिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के हर पहलू में शुद्ध आचरण करना चाहिए. शिरडी में बाबा के पास हर वर्ग के सरकारी और आम आदमी अपने सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष के लिए सहायता एवं आशीर्वाद लेने प्रायः आया जाया करते थे, जैसे कि मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मामलतदार, पुलिस अधिकारी, वकील, भक्त आदि. बाबा अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को किसी जाति, धर्म, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के बिना मदद देते थे. साथ ही हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उपदेश देते थे.

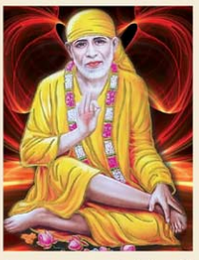

बाबा के द्वारा विभिन्न भक्तों को दिये गये उपदेशों में मूलतः एक उपदेश प्रधान रूप से मिलता है और वह उपदेश था कि धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक या व्यावसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा को अपनाया जाए. उपर्युक्त मजिस्ट्रेट को अपने जीवन में नैतिक आचरण की शिक्षा देने के पीछे बाबा का एक संदेश देखने को मिलता है और वह संदेश है कि जीवन के अन्य पहलुओं में सत्यनिष्ठा का आचरण न करना व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन जाता है. इसलिए आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सम्पूर्ण जीवन के हर पहलू में सत्यनिष्ठा से उच्च नैतिक आचरण करने की आवश्यकता है.

आम जीवन में जैसा कि कभी-कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग मंदिरों एवं धार्मिक कार्यों में काफी दान देते हैं परन्तु अपने घर के नौकर की बीमार सन्तान के उपचार में थोड़ी सी मदद करने में कंजूसी करते हैं. इसी प्रकार कई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के पालन के लिए काफी समय या धन व्यय करते हैं, परन्तु असंख्य उदाहरण पर भीख मांगने वाले एक छोटे बच्चे को दुत्कारते हैं. इसी प्रकार असंख्य पर भीख मांगने वाले एक छोटे बच्चे को दुत्कारते हैं. इसी प्रकार असंख्य उदाहरण प्रायः देखने को मिलते हैं, जो कि यह प्रमाणित करते हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित सुगुण भी महज उनकी एक आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं. इस प्रकार की विसंगतियों को देखकर अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज के भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिकतर लोग इस विसंगत मार्ग को ही अपनाते हैं. परन्तु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है. इसलिए श्री शिरडी साईं बाबा ने अपने भक्तों को सदैव जीवन के हर पहलू में दया, सहनशीलता, त्याग एवं सत्यनिष्ठा आदि गुणें को हर परिस्थिति में अपनाने की शिक्षा दी. जिन मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम समय में अधिक हुई.

'श्री साईं सच्चरित्र' में ऐसे महानुभावों के चरित्रों का वर्णन देखने को मिलता है. उदाहरण के रूप में मेघा नामक एक गरीब रसोइये ने अपने जीवन में बाबा के उपदेशों के अनुसार अत्यंत सरल भाव से जीवन-यापन करते हुए उच्च कोटि की आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त की. बाला साहेब भाटे एवं काका साहेब दीक्षित सांसारिक जंजाल से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर शिरडी में बाबा की चरणाश्रित रहे और म्हालसापति ने सम्पूर्ण जीवन में 'अपरिग्रह' का आचरण किया. 'श्री साईं सच्चरित्र' में ऐसे अन्य कई महानुभावों के विषय में वर्णन हुआ है.

इसीलिए बाबा के अनुयायी भक्तों को हर परिस्थिति में हर कर्म में सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता का आचरण जीवन में लाने की आवश्यकता है. इस प्रकार की जीवन-धारा को अपनाना सहज नहीं है, परन्तु बाबा के लिए जिनकी 'श्रद्धा' एवं 'सबूरी' अटूट है, वे क्रमशः इस मार्ग पर प्रगति करेंगे. ■

साईं भक्तों!
चौथी दुनिया व्यूरो
feedback@chauthiduniya.com
आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मालूम, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और दर्शन आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

कीवियों के ख़िलाफ़ भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया दम

टेस्ट में बेस्ट

सैयद मोहम्मद अब्बास

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में पराजित करते हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़ कर नम्बर वन का तमगा दोबारा हासिल कर लिया है. टेस्ट में बेस्ट होने के लिए टीम इंडिया ने अब मजबूती से कदम बढ़ा दिया है. दरअसल घरेलू पिचों पर भारतीय टीम हमेशा नम्बर वन रही है. अभी हाल में वेस्टइंडीज को धूल चटाने वाली विराट की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद मजबूत लग रही है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर अपनी धरती पर गजब का खेल दिखाया है. विराट की सेना ने उम्मीद के मुताबिक कीवियों का शिकार करते हुए नम्बर वन का खिताब भी हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में पराजित करते हुए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़ कर नम्बर वन का तमगा दोबारा हासिल कर लिया है. टेस्ट में बेस्ट होने के लिए टीम इंडिया ने अब मजबूती से कदम बढ़ा दिया है. दरअसल घरेलू पिचों पर भारतीय टीम हमेशा नम्बर वन रही है. अभी हाल में वेस्टइंडीज को धूल चटाने वाली विराट की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद मजबूत लग रही है. कानपुर टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम ने कोलकाता में केवल चार दिनों में मैच समाप्त कर अपनी काबीलियत का लोहा मनवाया है. कोलकाता टेस्ट में हालांकि बल्लेबाजी में टीम इंडिया को संघर्ष करना पड़ा लेकिन गेंदबाजी में उसकी शानदार रही. स्पिनरों ने जहां एक ओर शिकंजा कसा तो दूसरी ओर तेज गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया. पहले टेस्ट में स्पिनरों का रोल बेहद अहम था जबकि दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाजों ने कीवियों को सम्भलने का मौका तक नहीं दिया. बात अगर कीवियों की की जाये तो उनके बल्लेबाज यहां के हालात में नाकाम साबित हो रहे हैं. गेंदबाजी में उनके तेज गेंदबाज उम्मीद के मुताबिक स्विंग हासिल करने में कामयाब रहे. पहले और दूसरे टेस्ट में उनके तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को कई मौकों पर परेशान किया है. कोलकाता टेस्ट की बात की जाये तो तेज गेंदबाजों ने बेहद शानदार गेंदबाजी की. कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया ने खेल के हर प्रारूप में जानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 178 रन से पराजित कर सीरीज भी अपने नाम किया जबकि कानपुर में 500वें टेस्ट में भी टीम इंडिया ने यादगार प्रदर्शन कर कीवियों को चित कर दिया.

कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया ने घरेलू मैदान के 250वें टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी तरह से पहली पारी में 316 रन बनाये. कीवी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन जवाबी हमले में उनके बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और पहली पारी में केवल 204 रन पर ढेर हो गई. भुवी ने कीवियों को अपनी स्विंग के सहारे खूब छकाया. भुवी ने पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट चटकाये. दूसरी ओर मोहम्मद शमी ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाये. दूसरी पारी में भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर दिखी और केवल 263 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. एक समय टीम इंडिया ने छह विकेट केवल 106 रन के स्कोर पर चलते बने लेकिन बाद में रोहित शर्मा व साहा ने पारी को सम्भालते हुए टीम इंडिया को किसी तरह 263 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. गौरतलब है कि रोहित का बल्ला इससे पहले खामोश चल रहा था. उन्होंने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी कर भारत की जीत में अहम योगदान दिया. उन्होंने इस मैच की दूसरी पारी में 82 रन की जुझारू पारी खेली. रोहित ने पहली पारी में सस्ते में आउट हुए थे. दूसरी ओर साहा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से लोगों को प्रभावित किया. चोटी के बल्लेबाजों के पावेलियन लौटने के बाद साहा ने सम्भल कर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 54 रन का योगदान दिया जबकि दूसरी पारी में पचासा लगाते हुए नाबाद 58 रन की पारी खेली. माही के टेस्ट क्रिकेट संन्यास के बाद साहा उनकी कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं. बतौर बल्लेबाज व विकेट कीपिंग का जिम्मा निभाने वाले साहा को अभी लम्बा सफर तय करना है. टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाजों की बात की जाये तो उनमें विराट का बल्ला अब तक इस सीरीज में सुस्त पड़ा है. उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं. कानपुर टेस्ट में उनके बल्ले ने कोई खास नहीं किया है. हालांकि यह बात भी सत्य है कि उनका बल्ला ज्यादा दिन तक खामोश नहीं रहता है. बात सलामी बल्लेबाजों की जाये तो उनमें शिखर धवन ने काफी निराश किया है. चोट के चलते भी वह काफी परेशान रहे हैं. कोलकाता टेस्ट में उन्हें मौका मिला था लेकिन वह इस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं रहे. पहली पारी में भी एक रन के स्कोर पर चलते बने थे. दूसरी पारी में भी 17 रन के योग पर आउट हो गए थे. गौतम गम्भीर की जगह उनको इस मुकाबले में मौका दिया गया था. दूसरे सलामी बल्लेबाज मुरली विजय भी कोलकाता टेस्ट में फ्लाप रहे. मध्यक्रम में रहाणे का बल्ला कुछ मौकों पर चला, वहीं पुजारा अक्सर भारतीय पिचों पर रन बनाते दिख जाते हैं. टीम इंडिया की अगली दीवार बनने की ओर अग्रसर पुजारा को अभी बहुत कुछ साबित करना है. मध्यक्रम में बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाने वाले पुजारा रोहित की तरह विदेशों में रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं. हालांकि इस सीरीज में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक रन बना रहा है. कोलकाता टेस्ट में पहली पारी में 87 रन बनाये जबकि पहली पारी में नाकाम थे. वहीं कीवियों की बात की जाये तो भारत के खिलाफ कमजोर दिख रही है. तीन बल्लेबाजों पर निर्भर रहने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा है. टेलर और गुप्टिल जैसे बल्लेबाजों के रन न बनाने के चलते कीवियों को भारी नुकसान हुआ है.

खेल के हर क्षेत्र में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले अव्वल रही है. बतौर बप्तान विराट कोहली ने भी अपनी अलग पहचान बनायी है. अभी हाल में पाकिस्तान की टीम नम्बर वन बनी थी लेकिन भारत ने घरेलू सीरीज में जीत दर्ज कर पाक को नीचे धकेल दिया है. रिकॉर्ड के आइने पर गौर किया जाये तो इस सीरीज में कई रिकॉर्ड भी बने हैं. भारतीय क्रिकेट इतिहास में कानपुर टेस्ट काफी अहम था. 500वें टेस्ट के रूप में टीम इंडिया ने इस बार इसे और खास बनाते हुए पूर्व कप्तानों को भी सम्मानित किया. घरेलू मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है. इतिहास के पन्नों को पलटे तो इससे पता लगता है कि 1977 से 80 के बीच खेली गई कई टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 20 टेस्ट में नहीं हारा था. इससे पूर्व 1960-64 के बीच टीम इंडिया ने अपनी धरती पर 16 टेस्ट में जीत दर्ज कर दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया था. इस दौरान 13 टेस्ट में टीम इंडिया ने हारी नहीं थी. दूसरी ओर कोलकाता टेस्ट के पूर्व मैच में टीम इंडिया ने 14 खिलड़ियों को पगबाधा यानी एलबीडब्लू किया जबकि 1996-97 में एक बार 13 खिलाड़ी एलबीडब्लू हुए थे. इससे पूर्व कानपुर टेस्ट में कई रिकॉर्ड बने. उनमें सबसे प्रमुख रहा आर अश्विन का जानदार प्रदर्शन. अश्विन ने 37वें टेस्ट में 200 विकेट लेने का कारनामा पूरा कर लिया. वहीं बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने 33 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार कर लिया. कुल मिलाकर टीम इंडिया ने अपनी धरती पर एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया. विराट की कप्तानी भी एक बार फिर शानदार रही है. विराट को अभी बतौर बप्तान लम्बी पारी खेलनी है. ■

साहा ने जगायी उम्मीद

भारतीय क्रिकेट टीम में धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विकेट कीपिंग को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई थी लेकिन हाल के दिनों उनकी जगह शामिल रिद्धिमान साहा ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को बड़ी राहत दी है. साहा इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में से एक है. विराट कोहली ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे. साहा ने न्यूजीलैंड सीरीज से पूर्व वेस्टइंडीज में शतक जमाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा भी मनवाया था. अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भी दोनों पारियों में अर्धशतक जमाकर भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया. दरअसल साहा ने उस समय रन बनाये जब टीम इंडिया की हालत खस्ता थी. साहा के प्रदर्शन का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस साल खेले गई सात टेस्ट पारियों में दो अर्धशतक और एक शतक लगाकर बतौर बल्लेबाज भी अपने को साबित किया है. साहा ने अब तक 17 टेस्ट मैचों में 684 रन बनाये. साहा को वन डे में धोनी की वजह से कम मौके मिल रहे हैं. साहा ने पहली बार साल 2010 में टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिला. दरअसल, नागपुर टेस्ट में रोहित शर्मा के अनफिट होने के बाद उन्हें बतौर बल्लेबाज टीम में मौका दिया गया. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले के पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल सके. दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी के सामने थोड़ा संघर्ष किया और 36 रन का स्कोर बनाया. साहा ने घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है. इसके बाद उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला. उन्होंने बंगाल की तरफ से खेलते हुए डेब्यू रणजी मैच में शतक लगाकर खूब वाहवाही लूटी थी. इसके बाद साहा ने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया. भारत में विकेट कीपिंग की बात की जाये तो धोनी अव्वल माने जायेंगे. इससे पूर्व भारतीय टीम कई विकेट कीपरों को अजमा चुकी है. उनमें दिनेश कार्तिक का नाम भी शामिल है. कार्तिक भी बतौर बल्लेबाज टीम में अपना दावा ठोंकते रहे हैं लेकिन, साहा के मौजूदा प्रदर्शन से टीम में उनकी जगह और मजबूत हुई है. भारतीय टीम में विकेट कीपिंग को लेकर शुरू से माथापच्ची होती रही है. मध्यक्रम में विकेट कीपर बल्लेबाज टीम को मजबूती देने का काम करता है. हाल के दिनों साहा के आलावा भी कई विकेट कीपर है जो टीम इंडिया के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं. नमन ओझा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी विकेट कीपिंग के साथ-साथ मजबूत बल्लेबाजी करने का भी हुनर रखते हैं. इसके आलावा केएल राहुल भी बतौर विकेट कीपर असरदार साबित हो सकते हैं. मौजूदा दौर में केएल राहुल टेस्ट और वन डे दोनों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. कुल मिलाकर देखा जाये तो साहा को लम्बे समय तक टीम में बने रहना है तो लगातार अपने प्रदर्शन सुधार करना होगा. साहा में थोड़ी निरन्तर की कमी देखी जा सकती है. ■

फ़वाद खान ने दी सफाई

फ़वाद खान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और हाल ही में हुई घटनाओं पर बात की. लेकिन लोगों की मानें तो फ़वाद खान कायर और बुज़दिल हैं. ना वो पाकिस्तान के सगे निकले ना ही भारत के. फ़वाद खान ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मैं जुलाई से लाहौर में हूं और अपने दूसरे बच्चे के जन्म का इंतज़ार कर रहा था. इतने महीनों में ये मैं पहली बार कुछ बोल रहा हूं, इसलिए इसके पहले आपने जो भी मेरे नाम से सुना है वो गलत है. फ़वाद खान ने बयान तो जारी कर दिया लेकिन ये नहीं लिखा कि बात किस बारे में हो रही थी. हालांकि उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि वो चाहते हैं कि अमन पूरी दुनिया में बरकरार हो और उनके बच्चे ही इस बात को सुरक्षित करेंगे कि ऐसा ज़रूर हो.

गौरतलब है कि उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम करने पर बैन किया गया है और इस पर बॉलीवुड दो भाग में बंट गया है.

अजय नहीं करेंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और भारत की पूरी कोशिश है कि वह पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग जल्द से जल्द कर दे. जिसमें वह कामयाब होता नज़र आ भी रहा है.

अजय देवगन के अलावा बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं किसने क्या कहा?

हमें सेना के जवानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत

अमिताभ बच्चन का पाकिस्तानी कलाकारों को दिया गया यह एक बड़ा बयान है.

पाक कलाकारों को बैन करने के संबंध में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह इस बारे में बात करने का सही समय है. सीमा पर हो रही घटनाओं से देशवासी नाराज़ हैं और इस वक्त हमें उन जवानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है जो हमारी सुरक्षा की ख़ातिर अपनी जान गंवा रहे हैं.

अक्षय ने कहा– शर्म करो

सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने को लेकर देश में एक बहस चल रही है. अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने इसका सबूत देने की मांग भी की. इस पर अक्षय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा– पिछले कुछ दिनों से जो मेरे दिमाग़ में है, वह मैं यहां शेयर कर रहा हूं. मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है.''

अक्षय ने वीडियो में कहा– आज मैं आपसे सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं. आज मैं एक आर्मी मैन के बेटे की तरह बात कर रहा हूं. कई दिनों से मैं सुन रहा हूं कि अपने ही देश के लोग अपनों से बहस कर रहे हैं. कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, तो कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने की मांग कर रहा है. अरे शर्म करो. अरे यार ये बहस बाद में कर लेना.'' शर्म कर लो थोड़ी सी. 20 जवान उड़ी अटैक में शहीद हो गए और आप यहां मुद्दे ढूंढ़ रहे हैं. एक 24 साल का जवान नितिन यादव शहीद हो गया आपके लिए. उसके परिवार को ये चिंता नहीं है कि आपकी फिल्म रिलीज़ होगी कि नहीं.

सलमान खान– पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन

सलमान ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये जो होना चाहिए था वह अमन और शांति होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो गया है तो अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. लेकिन यह सब प्यार-मुहब्बत, अमन और शांति का पैगाम होता तो सभी के लिए अच्छा होता.

सलमान ने आगे पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करते हुए कहा कि कहा कि इन्हें सरकार ही तो इन्हें परमिट और वीजा देती है इसलिए यह भारत आते हैं. ये लोग तो कलाकार हैं, कोई टेररिस्ट नहीं. टेररिस्ट और कलाकार दोनों अलग-अलग सबजेक्ट है, आप क्या मानते हैं ये कलाकार टेररिस्ट हैं?

फिल्म क़यामत में अजय ने एक डायलॉग बोला था *जब बात हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की हो रही हो तो हर हिन्दुस्तानी एक ही तरफ होता है (हिन्दुस्तान की ओर)*... यह बात आज बिल्कुल सही साबित होती नज़र आ रही है. आज लगभग सभी भारतीय लोग सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय जवान और सरकार के साथ है लेकिन इसमें भी कुछ राजनेता अपनी राजनीति करने से बाज़ नहीं आ रहें है. ख़ैर अजय ने भारतीय जवानों का समर्थन करते हुए साबित भी कर दिया कि वह अच्छे स्टार होने के साथ एक सच्चे देशभक्त भी है. जिस पर उनके फैंस उन पर नाज़ है.

अजय देवगन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह फिलहाल किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहते. भारत-पाक के बीच मौजूदा माहौल को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? जब लगातार गोलियां चल रही हैं, इस समय पर तो नहीं. अजय ने आगे कहा कि आप बातचीत कर रहे हैं और कोई आकर आपको थप्पड़ मार दे, तो बात कैसे जारी रखेंगे? जब उनसे पूछा गया कि क्या वे प्रो-बीजेपी लाइन ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तब भी वैसा ही करता, जब कोई और सरकार होती.

अजय देवगन ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा– आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, बातचीत होनी चाहिए. लेकिन आप बातचीत कर रहे हैं और कोई आपको आकर मार रहा है. आप कैसे बातचीत जारी रखेंगे? मैं देखना चाहता हूं कि आप बात कर रहे हों और कोई आपको कसकर थप्पड़ रसीद दे तो आप क्या करेंगे, उससे बात करते रहेंगे या जवाब देंगे?

उड़ी आतंकी हमले में 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी (एमएनएस) ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किए जाने की मांग की. मनसे ने इन कलाकारों को धमकी दी थी कि वे भारत छोड़ दें. कई कलाकारों और ऑर्गेना-इजेशन्स ने मनसे की मांग का समर्थन किया. इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने का फैसला किया.■

जूही बोलीं–हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है

जूही चावला ने कहा– यह सब जो हो रहा है, उससे लगता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है. हम प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हमें लोगों के सोचने का तरीका बदलना होगा.

नाना ने कहा था–पहले मेरा देश है

नाना पाटेकर ने कहा– मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कलाकार बाद में, पहले मेरा देश. देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं. कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने (छोटे) से हैं. इस मसले पर जो लोग पटर-पटर कर रहे हैं, उन्हें महत्व मत दो. मैं किसके बारे में कह रहा हूं, आप जानते हैं. नाना पाटेकर ने साफ कहा कि मुझे बॉलीवुड से कोई मतलब नहीं है. देश से बढ़कर कोई स्टार नहीं होता. कोई कलाकार नहीं होता. हम लोग तो नकली हीरो हैं, हमारे जवान असली हीरो हैं.

जब लगातार गोलियां चल रही हैं, इस मोमेंट पर तो नहीं. आप बातचीत कर रहे हैं और कोई आकर आपको थप्पड़ मार दे तो बात कैसे जारी रखेंगे?

नूर में सोनाक्षी ने पाकिस्तानी पत्रकार की भूमिका से किया इंकार

मैं पाकिस्तानी पत्रकार की भूमिका में नहीं हूं. फिल्म किताब पर आधारित है, जो पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखित है. कहानी को मुंबई के बैकग्राउंड पर ढाला गया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वह फिल्म नूर में पाकिस्तानी पत्रकार की भूमिका में नहीं हैं. यह फिल्म पाकिस्तान की सबा इम्तियाज़ के नॉवेल *कराची यू आर किलिंग मी* पर आधारित है. आने वाली फिल्म *फोर्स 2* के प्रमोशन पर सोनाक्षी ने फिल्म नूर में अपने किरदार के बारे में बातचीत की. इस पर उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि मैं इसमें पाकिस्तानी पत्रकार की भूमिका में नहीं हूं.

फिल्म किताब पर आधारित है, जो पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखित है. कहानी को मुंबई के बैकग्राउंड पर ढाला गया है. यह फिल्म मुंबई में नूर के दुर्भाग्य और प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. पूरब कोहली, शिवानी दांडेकर और कनन गिल स्टार फिल्म बड़े पर्दे पर अगले साल सात अप्रैल को रिलीज़ होगी.

इसकेअलावा, सोनाक्षी फिल्म *अकीरा* के बाद *फोर्स 2* में भी अपना मारधाड़ वाला अंदाज में नज़र आएंगी.■

अनचाहे किस्से

शादी के बाद भी रहा था रीना से शत्रुघ्न का अफेयर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर, 1945 को पटना में हुआ. शत्रुघ्न सिन्हा एक अभिनेता होने के साथ-साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं. उनकी पास (1971), दोस्त (1974), काला पत्थर (1979), दोस्ताना (1980) जैसी हिट फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके शत्रुघ्न की पर्सनल लाइफ काफी चर्चित रही है. 1980 में उन्होंने पूर्व मिस यंग इंडिया रही पूनम चंडीरामणि (अब सिन्हा) से शादी की. यह वह दौर था, जब शत्रुघ्न का नाम रीना राय से जोड़ा जा रहा था. दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया. शत्रुघ्न और रीना के अफेयर के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में फैले हुए थे. रीना से शत्रुघ्न का रिश्ता 7 सालों तक चला. दिलचस्प बात यह थी कि एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वे अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब जानती थीं.

शत्रुघ्न की शादी से चौंक गईं रीना

बॉलीवुड में जिस समय रीना राय का करियर अपने चरम पर था, उस वक्त उनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चल रहा था. किसी काम के सिलसिले में जब रीना लंदन गई हुई थीं, तो शत्रुघ्न ने पूनम से शादी कर सबको चौंका दिया था. जब रीना को शादी की ख़बर लगी तो वो भड़क गईं और तुरंत वापस आकर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से इसका ज़वाब मांगा. शादी के कई सालों बाद तक भी शत्रुघ्न सिंहा रीना राय से मिलते रहे. लेकिन इस रिश्ते का दुखद अंत क्यों हुआ, इसका ज़वाब कोई नहीं जानता.

7 सालों तक रहा रिश्ता

एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना के रिश्ते की बात को कबूलते हुए कहा था, रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल और इंटेंस रहा है. लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गईं. लेकिन मेरी मानें तो यह बढ़ गई हैं. मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल मुझे दिए.

रीना की मां की चाहत : शत्रुघ्न की दूसरी पत्नी बनें बेटी...

रीना राय की मां चाहती थी कि उनकी बेटी शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी पत्नी बनें. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं भगवान से दुआ करती हूं कि शत्रुघ्न मेरी बेटी को अपनी दूसरी पत्नी की तरह स्वीकारें. वे उनसे प्यार नहीं, बल्कि उन्हें बेवकूफ बनाते थे. हालांकि, रीना को लगता था कि यह प्यार है. लेकिन मैंने कहा था कि यह गलती है.

शादी के बाद भी रीना से रहे शत्रुघ्न से संबंध

एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम ने कहा था कि जब मुझे दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट गई थी. लेकिन शत्रु ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे, जिनपर वे विश्वास नहीं करते थे. मैं यह बात जानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेयर चला.■